22 जुलाई, 2026 बुधवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 111

RNI No. DELMUL/2012/47011

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

युवराज सिंह ने यशस्वी को पर्याप्त अवसर नहीं मिलने पर जताई चिंता 07

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में किसानों का दिल्ली कूच

शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात

वेब वार्ता, नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में एक तरफ जहाँ पेपर लीक के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों के कारण माहौल गर्म है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब से किसानों का बड़ा हुजूम दिल्ली की ओर रवाना हो चुका है। किसान भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते का कड़ा विरोध कर रहे हैं। हालांकि, दिल्ली पहुँचने से पहले ही हरियाणा पुलिस ने किसानों को पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सरकार किसानों को दिल्ली में महापंचायत करने से रोक रही है और दमनकारी नीति अपना रही है।

किसानों के इस आंदोलन को देखते हुए पंजाब-हरियाणा सीमा और घग्गर नदी के पुलों पर पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई है। देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले पंजाब के विभिन्न हिस्सों से बसों और अन्य वाहनों में सवार होकर निकले किसान दिल्ली स्थित किसान घाट पहुँचकर एक दिवसीय महापंचायत करना चाहते हैं। फतेहगढ़ साहिब से करीब एक हजार से अधिक किसानों का जत्था सरहिंद होते हुए शंभू बॉर्डर पहुँचा है। किसान नेताओं का कहना है कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति का जायजा लेने और परस्पर बातचीत करने के बाद ही आगे के ठोस कदम पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है

दूसरी ओर, स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए हरियाणा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चढूनी को कुरुक्षेत्र में दिल्ली कूच करने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। किसानों का दावा है कि राज्य पुलिस बड़े पैमाने पर किसान कार्यकताओं को हिरासत में ले रही है। किसानों की मुख्य चिंता यह है कि अमेरिका के साथ होने जा रहे इस व्यापार समझौते से देश में कृषि और अन्य विदेशी सामान बेहद सस्ती कीमतों पर आयात होने लगेगा। इससे भारतीय किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पाएगा, जिसका सीधा और प्रतिकूल असर देश के किसानों तथा खेतिहर मजदूरों पर पड़ेगा। किसानों ने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करते हुए इस प्रस्तावित व्यापार समझौते को पूरी तरह रद्द करने और देश के आम किसानों तथा मजदूरों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

8वां वेतन आयोग

फिटमेंट फैक्टर 2.0 का गणित, दोगुनी नहीं होगी पूरी सैलरी!

वेब वार्ता, नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग के इंतजार में बैठे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में यह सवाल स्वाभाविक है कि उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। अक्सर माना जाता है कि अगर सरकार 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तब कर्मचारियों की पूरी सैलरी दोगुनी हो जाएगी। हालांकि, यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है।

दरअसल, फिटमेंट फैक्टर केवल मूल वेतन (बेसिक सैलरी) पर लागू होता है, जबकि कर्मचारी के हाथ में आने वाली कुल सैलरी (ग्रॉस सैलरी) में कई तरह के भत्ते भी शामिल होते हैं। इसकारण बेसिक वेतन में भले ही 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन ग्रॉस सैलरी में उतनी वृद्धि नहीं दिखती। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी केवल मूल वेतन से नहीं बनती, बल्कि इसमें महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (टीपीटीए) और अन्य कई भत्ते शामिल होते हैं। जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तब महंगाई भत्ता आमतौर पर नए बेसिक वेतन में समायोजित होकर शून्य से शुरू होता है। एचआरए नए बेसिक के आधार पर तय होता है, लेकिन कई अन्य भत्तों में तत्काल समान अनुपात में बढ़ोतरी नहीं होती, जिससे कुल सैलरी की वृद्धि सीमित रह जाती है।

पिछले वेतन आयोगों का रिकॉर्ड भी इस बात की पुष्टि करता है। चौथे वेतन आयोग में ग्रॉस सैलरी में लगभग 27.60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि पांचवें में यह 31 प्रतिशत रही। छठे वेतन आयोग में 1.86 फिटमेंट फैक्टर के बावजूद ग्रॉस सैलरी में करीब 54 प्रतिशत का इजाफा हुआ। वहीं, सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिलने के बाद भी कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी औसतन केवल 14.29 प्रतिशत ही बढ़ी। यह स्पष्ट करता है कि फिटमेंट फैक्टर जितना बड़ा हो, ग्रॉस सैलरी में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी, यह जरूरी नहीं है।

संक्षिप्त वार्ता

रूस-यूक्रेन युद्धः मिसाइल हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत

ओडेसा। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हुए कमर्शियल जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए रूसी मिसाइल हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। 17 सदस्यीय चालक दल वाले इस जहाज पर 5 भारतीय सवार थे। इस भीषण हमले में कुल 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है।

भारत सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए स्थिति पर गहरी नजर बनाए रखने और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। नौवहन निदेशालय के नियमों के अनुसार, यदि किसी भारतीय नाविक की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को डेथ ऑन बोर्ड बेनिफिट स्कीम के तहत 6 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना सीफेयरर वेलफेयर फंड सोसाइटी द्वारा संचालित होती है।

सिक्किम में NHPC की निमार्णाधीन सुरंग ढही, 10 श्रमिकों की मौत

गुवाहाटी/नामची। सिक्किम के नामची जिले में एनएचपीसी की तीस्ता स्टेज-6 जलविद्युत परियोजना की निमार्णाधीन सुरंग में हुए भीषण हादसे में अब तक 10 श्रमिकों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य श्रमिक अभी भी सुरंग के भीतर फंसे हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग के भीतर मीथेन गैस के विस्फोट के बाद भूस्खलन हुआ, जिससे सुरंग का प्रवेश मार्ग बंद हो गया और अंदर मौजूद श्रमिक बाहर नहीं निकल सके। बताया गया कि हादसा सोमवार दोपहर करीब 3:40 बजे ज्होलुंगे क्षेत्र के समरदुंग स्थित निमार्णाधीन सुरंग में हुआ। घटना के समय कुल 25 श्रमिक, जिनमें एनएचपीसी के कर्मचारी भी शामिल थे, सुरंग के भीतर काम कर रहे थे।

पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी

जंतर-मंतर की घटना के विरोध में छात्र आंदोलन को समर्थन

वेब वार्ता, नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस द्वारा की गई बर्बर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को अपना आंदोलन तेज कर दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री आवास के निकट धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने छात्र आंदोलन के प्रति एकजुटता जताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

कांग्रेस का कहना है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हुई पुलिस की बर्बर कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। इसी के विरोध में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हालिया घटनाओं को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग दोहराई। प्रियंका गांधी भी धरने में शामिल रहीं और प्रदर्शनकारियों के प्रति समर्थन व्यक्त किया।

कांग्रेस नेताओं का यह धरना ऐसे समय में हुआ है, जबकि जंतर-मंतर पर युवाओं ने पुनः धरना-प्रदर्शन शुरू कर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है। बीते रोज की घटना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। पार्टी का आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बल प्रयोग किया गया, जबकि सरकार को उनकी शिकायतों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था। धरने के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई। प्रदर्शन को देखते हुए क्षेत्र में यातायात पर भी आंशिक प्रभाव पड़ा।

नीट पेपर लीक मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा-मोदी

नई दिल्ली, वेब वार्ता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को संसद भवन हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि गड़बड़ी की खबरें मिलने पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की गई। तेरह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा विद्यार्थियों के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए बिना किसी देरी के दोबारा परीक्षा कराई गई और नतीजे घोषित किए गये। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक मामले को रोकना सिर्फ सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है। इसके खिलाफ राज्य सरकारों और सभी दलों को मिलकर लड़ना होगा। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि श्री मोदी ने भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जा रहे कड़े कदमों के बारे में भी जानकारी दी है।

संसद मार्च में हिंसा करने वालों पर पुलिस ने की एफआईआर

नई दिल्ली, वेब वार्ता

राजधानी नई दिल्ली में सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान भयंकर बवाल हुआ है। इस हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने अलग-अलग घटनाओं के आधार पर कई एफआईआर दर्ज करके अपनी मामले की जांच तेज कर दी है।

इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बार-बार दी गई चेतावनी को पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया। हिंसक भीड़ ने जानबूझकर लागू निषेधाज्ञा का गंभीर उल्लंघन करते हुए पुलिस बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर भारी पथराव किया और कई सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस हिंसक और जानलेवा हमले में कई वरिष्ठ अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस वाले घायल हुए हैं।

118 पुलिसकर्मी हुए घायल

इस हिंसक भीड़ के भयंकर पथराव और हमले में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी बहुत ही बुरी तरह से घायल हुए हैं। इनमें स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और डीसीपी रैंक के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी पूरी तरह शामिल हैं। इसके अलावा कई महिला पुलिसकर्मियों को भी ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से कई चोटें आई हैं। घायल जवानों का अस्पताल में मेडिको-लीगल जांच (एमएलसी) और इलाज बहुत ही तेजी से किया जा रहा है।

20 सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़

हिंसक भीड़ ने पुलिस और आम जनता की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही गंभीर और बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। इस घटना के दौरान लगभग 15 से 20 सरकारी गाड़ियों को बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उपद्रवियों ने सार्वजनिक संपति को भारी नुकसान पहुंचाया और बड़े पैमाने पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

70 प्रदर्शनकारी हिरासत में

पुलिस और भीड़ के बीच हुई इस भारी हाथापाई में लगभग 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। पुलिस ने मौके से सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 70 उग्र प्रदर्शनकारियों को तुरंत हिरासत में ले लिया है। इन सभी उपद्रवियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और अन्य लागू कानूनों के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस हिंसा में शामिल अन्य लोगों की भी वीडियो फुटेज के जरिए बहुत बारीकी से पहचान कर रही है।

युवाओं के साथ पुलिस का व्यवहार बेहद शर्मनाक

नई दिल्ली। नीट से जुड़े विवाद और 20 जुलाई को दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ पुलिस के व्यवहार को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को बल प्रयोग करने के बजाय छात्रों की बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

भारत को रूस का ऐतिहासिक जेट इंजन ऑफर, अमेरिका हिल गया

वेब वार्ता, नई दिल्ली

मास्को से आई बड़ी खबर ने अंतरराष्ट्रीय रक्षा जगत में हलचल मचा दी है। रूस ने अपने हाल ही में विकसित किए गए सबसे अत्याधुनिक एएल51 एफ1 जेट इंजन का एक अभूतपूर्व ऑफर भारत को दिया है, इस आफर ने अमेरिका तक को चौंका दिया है। यह केवल एक बिक्री समझौता नहीं, बल्कि भारत को स्टेल्थ पावर में आत्मनिर्भर बनाने का एक सुनहरा मौका है। एएल51 एफ1 जेट इंजन को दुनिया एक मास्टरपीस मान रही है, जिसने दशकों से अमेरिकी स्टेल फाइटर इंजन के वर्चस्व को चुनौती दी है। यह इंजन न केवल फाइटर जेट को बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक रफ्तार (सुपरक्रूज) देता है, बल्कि इसका थ्रस्ट वेक्टरिंग और कम हीट सिग्नेचर रडार से ओझल रखने में मदद करता है। रूस ने भारत को केवल यह इंजन बेचने की बात नहीं की है, बल्कि एक व्यापक पैकेज पेश किया है। इस ऑफर में तकनीक साझाकरण (टेक शेयरिंग) शामिल है, जहाँ रूस इंजन के डिजाइन समाधान और विकास के अनुभव को भारत के साथ साझा करेगा। दूसरा, अगर भारत भविष्य में अपना स्टेल्थ इंजन विकसित करता है, तब रूस उसमें तकनीकी सहयोग का वादा कर रहा है। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु ब्रिज सप्लाई है जब तक भारत का अपना इंजन तैयार नहीं हो जाता, रूस एएल51 एफ1 जेट इंजन की निर्बाध आपूर्ति करेगा इस किसी भी देश द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पेशकश माना जा रहा है।

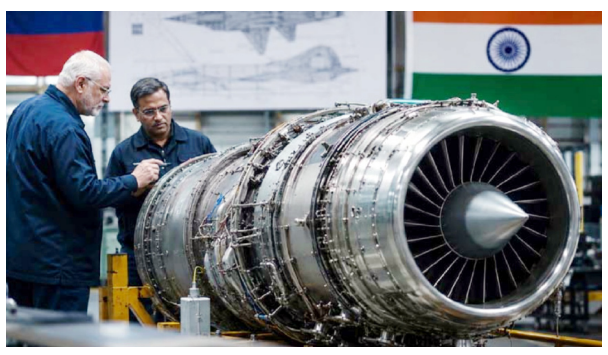

रूस के इस ऑफर की टाइमिंग बेहद अहम है। भारत काफी समय से अमेरिकी एफ414 इंजन का इंतजार कर रहा था, लेकिन हाल ही में खबरें आई थीं कि उनकी आपूर्ति को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया कि इन इंजनों को किसी और ग्राहक को दिया जा सकता है। इसके बाद भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा शून्य पैदा हो गया था। रूस ने इसी मौके को भांप लिया है। वह जानता है कि इंजन ही वहां कड़ी है जहाँ भारत को सबसे अधिक मदद की आवश्यकता है, और इसी डूबती नैया पर मरहम लगाकर रूस ने भारत को अपना सबसे बड़ा रक्षा भागीदार बनाए रखने का दांव खेला है।

दशकों की दूरी को कुछ सालों में तय कर लेगा

हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के इस ऑफर के पीछे एक बड़ा मकसद है। रूस चाहता है कि भारत उसके स्टेल्थ फाइटर जेट एसयू-57 की खरीद पर फिर से विचार करे, जिस अब तक बड़े अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर नहीं मिले हैं। भारत जैसा बड़ा खरीदार रूस के रक्षा उद्योग को पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच बेहद जरूरी ऑक्सीजन देगा। इसके अलावा, एएल51 एफ1 जेट इंजन के विकास पर खर्च किए गए अरबों डॉलर की भरपाई भी रूस भारत को इंजन बेचकर करना चाहता है। एक तरफ अमेरिका की आधुनिक लेकिन अनिश्चित तकनीक है, और दूसरी तरफ रूस का वह भरोसा और तकनीक जो भारत को आत्मनिर्भर बना सकती है। यदि यह समझौता होता है, तब भारत न केवल उन्नत इंजन तकनीक तक पहुंचेगा, बल्कि भविष्य के स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर के निर्माण में दशकों की दूरी को कुछ ही सालों में तय कर लेगा।

संपादकीय

दलबदल अर्थात जनादेश को ठेंगा

संसद के मानसून सत्र की शुरूआत नाटकीय और हास्यास्पद रही। विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस से बगावत करने वाले सांसदों को एनसीपीआई के प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। बैठक में सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष मौजूद थे। विपक्ष के सांसदों ने बहिर्गमन किया, मीडिया को अपने-अपने बयान दिए और करीब 15 मिनट के बाद बैठक में वापस भी चले गए। यह क्या हुआ? बहिष्कार करना था, तो पूरी सर्वदलीय बैठक को खारिज करना चाहिए था। यह बैठक भी महज औपचारिक होती है, क्योंकि सदन में कार्यवाही बिल्कुल उलट होती है। बहरहाल इस सत्र के दौरान कमोबेश लोकसभा में सांसदों की सीट का परिदृश्य पहले से बिल्कुल अलग दिखाई देगा। स्पीकर ओम बिरला ने 48 सांसदों की सीटें बदली हैं, जिनमें 22 सांसद द्रमुक के हैं। चूंकि तमिलनाडु में द्रमुक-कांग्रेस का संबंधविच्छेद हो चुका है, लिहाजा द्रमुक ने उनकी सीटें बदलने का आग्रह किया था। इन 48 सांसदों की सीटें सत्ता-पक्ष की तरफ हैं। क्या मान लिया जाए कि अब ये 48 सांसद सत्तारूढ़ एनडीए के प्रत्यक्ष या परोक्ष हिस्सा हो गए हैं? संसद के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है, लिहाजा यह सच भी सामने आ ही जाएगा। यकीनन सत्र हंगामेदार होगा, क्योंकि मुद्दों को लेकर कई विरोधाभास हैं। बेशक राम मंदिर में चढ़ावा-चोरी, पेपरलीक, परिसीमन, महंगाई, बेरोजगारी, किसानी, ई-20 एथेनॉल विवाद, विदेश नीति, वोट चोरी और वांगचुक अनशन आदि बेहद संवेदनशील और राष्ट्रीय फलक के मुद्दे हैं, लेकिन दलबदल का राजनीतिक चलन सीधा लोकतंत्र, चुनाव प्रणाली और जनादेश के लिए गंभीर चुनौती है। बल्कि जनादेश को ठेंगा दिखाया जा रहा है। क्या संसद के भीतर ऐसे मुद्दे पर चर्चा होगी और कोई निश्चित नीति तय की जाएगी? हमारा अनुभव कहता है कि ऐसा कदापि नहीं होगा। हमने लोकतंत्र के अभी तक के इतिहास में न तो पढ़ा है और न ही संसदीय कवरेज के दौरान देखा है कि जिस पार्टी का अस्तित्व ही गुमनाम हो, अचानक उसके पाले में 20 लोकसभा सांसद आ जाएं! यह काला चमत्कार ही हो सकता है! बिना चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़े, बिन उम्मीदवारी के और प्रत्यक्ष जनादेश हासिल किए बिना ही 20 सांसद! यानी औसतन 200 विधायक! बेशक यह लोकतंत्र पर कलंक है और दलबदल के जरिए राजनीतिक अस्थिरता का डरावना उदाहरण है।

साफ मायने हैं कि जनादेश कुछ भी हो, यदि आप सत्ता में हैं, तो किसी भी जनादेश को तोड़-फोड़ कर सदन में अपना आंकड़ा व्यापक कर सकते हैं। स्पीकर ने तृणमूल से टूटे 20 सांसदों के एनसीपीआई में विलय को मान्यता दी है और सत्ता-पक्ष के साथ उनकी नई सीटें तय की हैं और इस नए संसदीय दल के नेता, मुख्य सचेतक भी मनोनीत किए गए हैं। क्या हम इन्हें एनसीपीआई के सांसद मानें? लोकतंत्र तो ऐसी गवाही नहीं देता, बेशक स्पीकर ने मान्यता दे दी है। स्पीकर के सामने इन बागी सांसदों को अयोग्यकरार देने की याचिका अब भी विचाराधीन है। स्पीकर भी तो भाजपा के निर्वाचित सांसद हैं, लिहाजा उनकी राजनीतिक निष्ठाओं की परीक्षा होती रहती है। आप उन्हें बिल्कुल तटस्थ नहीं मान सकते। बहरहाल चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में ये सवालिया सांसद तृणमूल कांग्रेस के विजयी सांसद हैं, जिन्हें पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने अधिकृत पत्र देकर प्रत्याशी बनाया था। चुनाव में उन्हें जनादेश मिला, तो जून 2024 से अभी जुलाई, 2026 तक वे तृणमूल सांसद ही थे। कितनी भी बगावत कर लें अथवा दलबदल कर लें, लेकिन जनादेश तृणमूल प्रतिनिधि को ही दिया गया था। बेशक जनता हिसाब कर लेगी! सवाल यह है कि ऐसे लोकतांत्रिक यथार्थ को कैसे बदला जा सकता है? सर्वोच्च अदालत के पांच न्यायाधीशों, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ समेत, ने भी दलबदल पर जो फैसला दिया था, उसका उल्लंघन तो असंवैधानिक है। क्या स्पीकर ऐसे फैसले को नजरअंदाज कर सकते हैं? बेशक स्पीकर का निर्णय भी बेहद महत्वपूर्ण है और उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन अदालतें भी लेट-लतीफ हैं। एनसीपी और शिवसेना के मामले करीब चार साल बाद अब भी सर्वोच्च अदालत में लटके हुए हैं। राजनीतिक दल क्या कर सकते हैं? यदि सत्र के दौरान संसद में इस नाजुक मुद्दे पर कोई साझा निष्कर्ष सामने आ जाए, तो देशहित में ही होगा। यह चिंताजनक है कि दलबदल अब पहले से भी ज्यादा संख्या में हो रहा है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है।

बलूचिस्तान में स्वघोषित आजादी

रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से सोशल मीडिया पर एक स्वघोषित बयान और पत्र वायरल हुए हैं, जिसमें बलूच नेता मीर यार बलूच और कुछ पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहे संगठनों ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है। अपना नया झंडा और राष्ट्रगान जारी करते हुए सरकार बना लेने का दावा भी किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के लड़ाकों ने 27 पुलिसकर्मियों का आपहरण कर हत्या कर दी है। इससे बलूच आंदोलन उत्साहित हुआ है और वे जल्द कानूनी रूप में आजादी मिल जाने की उम्मीद करने लगे हैं। हालांकि इस हत्याकांड के बाद पाक सेना ने बलूचिस्तान में फ्रंटियर कोर, पुलिस व आतंकवाद निरोधक बल के साथ ऑपरेशन शाबान शुरू कर दिया है। पाक के सामने अब बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि बीएलए को इजरायली खुफिया एजेंसियों से धन, तकनीक और आधुनिक संचार उपकरण मिल रहे हैं। पाक सेना ने लडकों के पास से स्टारलिंग उपकरण जब्त किए हैं। पाक सेना का यह भी आरोप है कि अफगानिस्तान बीएलए को विद्रोही बलूचों ने करीब 85 प्रतिशत बलूचिस्तान की भूमि पर काबिज होने का दावा किया है। बलूच कार्यकताओं ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की अपील भी कर दी है। यह पाकिस्तान का वह प्रमुख क्षेत्र है, जहां से चीन-पाक आर्थिक गलियारा गुजर रहा है।

इसकी सुरक्षा और भविष्य को लेकर भी चचाएं शुरू हो गई हैं। यही वह क्षेत्र है जहां अत्यंत दुर्लभ खनिज एवं प्राकृतिक गैसें उपलब्ध हैं। यही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बलूचिस्तान प्रांत में लंबे समय से स्वतंत्रता की जो लड़ाई चल रही है, वह अब सफलता के शिखर पर है। बलूचिस्तान को नए देश के रूप में मान्यता मिल जाती है तो 1971 के बाद पाकिस्तान की भूमि पर दूसरा बड़ा विभाजन दिखाई देगा। 1971 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना को सैनिक मदद देकर पाक के दो टुकड़े कर दिए थे। अब बलूच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए दिल्ली में बलूचिस्तान का दूतावास खोलने की मांग कर रहे हैं। प्रसिद्ध लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता मीर यार बलूच को बलूच के लोगों के अधिकारों की वकालत के लिए जाने जाते हैं। बलूचों ने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में शांति रक्षक बल भेजने और पाक सेना को बलूच सीमा क्षेत्र से बाहर कर देने का आग्रह भी किया है। यदि बलूच स्वतंत्र देश बन जाता है तो भारत-पाक युद्ध के बीच 1971 की तरह एक युगांतरकारी घटना देखने को मिलेगी, जिसमें बलूचों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव में भारत भी भागीदार हो सकता है। बलूचों की स्वतंत्रता की संभावना का अहसास पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने भी जताया है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान पर अब सेना और सरकार का नियंत्रण ढीला पड़ रहा है। यहां के हालात इतने खराब हैं कि सरकारी मंत्री तक बाहरी सुरक्षा के बिना बाहर नहीं निकल सकते हैं। सेना के जवान अपने ही देश में बंकरों में छिपे हैं। बलूचिस्तान में विद्रोह की आग चरम पर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आजादी की मांग करने वाला सबसे पुराना सशस्त्र अलगाववादी संगठन है। यह संगठन पहली बार 1970 में अस्तित्व में आया था। इसने जुल्फिकार अली भुट्टो के कार्यकाल में बलूचिस्तान प्रांत में सशस्त्र विद्रोह का शंखनाद कर किया था।

कालांतर में सैनिक तानाशाह जिया उल हक द्वारा सत्ता हथियाने के बाद बलूच नेताओं के साथ बातचीत हुई, जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष विराम की स्थिति बन गई थी। नतीजतन बलूचिस्तान में सशस्त्र विद्रोह खत्म हो गया था और बीएलए का भी कोई वजूद नहीं रह गया था। किंतु कारगिल युद्ध के बाद सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्तापलट कर सत्ता हथिया ली। इसके बाद मुशर्रफ के संकेत पर साल 2000 में बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नवाबमिरी की हत्या कर दी गई और मुशर्रफ ने कुटिल चतुराई बरतते हुए पाक सेना से इस मामले में आरोपी के रूप में बलूच नेता खेरबक्ष मिरी को गिरफ्तार करा दिया। इसके बाद फिनिक्स पक्षी की तरह बीएलए फिर उठ खड़ा हुआ। जगह-जगह हमले शुरू हो गए। साल 2020 में एकाएक बीएलए की ताकत बढ़ गई और बलूचिस्तान के सरकारी प्रतिष्ठानों तथा सुरक्षाबलों पर हमलों की संख्या बढ़ती चली गई। बीएलए बलूचिस्तान में चीन के प्रभाव को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करता है। उसका मानना है कि चीन बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा को हड़पने का काम कर रहा है। इसी नजरिए से ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने के साथ एक बड़ा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी बना रहा है। दरअसल भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के समय बलूचिस्तान को बलूचों की इच्छा के बिना बंदूक की जोर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। जबकि वे स्वयं को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहते थे। अतएव पाक की स्वतंत्रता के समय से ही बलूचों का संघर्ष पाक सरकार और सेना से निरंतर बना हुआ है। बीएलए जब साल 2000 में वजूद में आया था तब इसके लड़ाकों की संख्या 6000 से भी ज्यादा थी। जिसमें करीब 150 आत्मघाती दस्ते शामिल थे। सरदार अकबर खान बुगती एक समय बलूचिस्तान के सर्वमान्य नेता रहे हैं। इसीलिए वे बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। 26 अगस्त 2006 को पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने उनकी हत्या कर दी थी। तभी से यह संगठन पाक सेना से लोहा ले रहा है।

वर्तमान में बलूच अलगाववादी और तालिबान के बीच निरंतर निकटता बढ़ रही है। वैसे भी अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के काबिज होने के बाद से पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। पाक सरकार ने भी स्वीकार किया है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ही बलूच लड़ाकों को प्रशिक्षित कर रहा है। बलूचिस्तान प्रांत में अब महिलाओं ने भी बीएलए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बलूच नागरिकों के दमन चक्र के विरुद्ध मोर्चा खोल लिया है। इस सच्चाई को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी स्वीकारा है। पाक की आजादी के साथ बलूचिस्तान का मुद्दा जुड़ा है। पाक की कुल भूमि का 43.6 फीसदी हिस्सा केवल बलूचिस्तान का है। लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है। करीब 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस हिस्से में सर्वाधिक बलूच हैं, पाक की कुल आबादी में इनकी छह प्रतिशत की भागीदारी है। इसका कुल क्षेत्रफल 347190 वर्ग किमी है। यहां हिंदू, सिख और ईसाई भी रहते हैं।

इनमें आपस में खूब भाईचारा है। भगवान शिव की पत्नी सती का हिंगलाज मंदिर इसी बलूच क्षेत्र में आता है। अनेक मुसलमान भी देवी सती की पूजा-अर्चना करते हैं क्योंकि ये धर्मांतरित हैं। यहां से कभी सांप्रदायिक दंगों की खबरें नहीं आती हैं। 1999 में परवेज मुशर्रफ सत्ता में आए तो उन्होंने बलूच भूमि पर सैनिक अड्डे खोल दिए। इसे बलूचों ने अपने क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश माना और फिर से संघर्ष तेज हो गया। इसके बाद यहां कई अलगाववादी आंदोलन वजूद में आ गए। इनमें सबसे प्रमुख बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। पीओके और बलूचिस्तान पाक के लिए बहिष्कृत क्षेत्र हैं। पीओके की जमीन का इस्तेमाल वह, जहां भारत के खिलाफ शिविर लगाकर गरीब व लाचार मुस्लिम किशोरों को आतंकवादी बनाने का प्रशिक्षण देता रहा है, वहीं बलूचिस्तान की भूमि से खनिज व तेल का दोहन कर अपनी आर्थिक स्थिति बहाल किए हुए है। यहां सोना, तांबा, कोयला और प्राकृतिक गैसों के बड़े भंडार हैं, लेकिन इनसे कमाई का बड़ा हिस्सा पाक सरकार, सेना और चीनी कंपनियां हथिया लेती हैं। इस कारण लोगों का गुस्सा उबाल पर है। बलूच अब अलग देश बनाने के लिए आंदोलन पर उतारू हैं। संभवतः बलूच जल्द ही आजाद हो जाएंगे।

प्रमोद भार्गव
स्वतंत्र लेखक

कैंसर की महंगी दवाएं—जीवन का अधिकार बनाम इलाज की कीमत

कैंसर आज केवल एक गंभीर बीमारी नहीं, बल्कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। चिकित्सा विज्ञान ने कैंसर के उपचार में उल्लेखनीय प्रगति की है और नई जीवनरक्षक दवाओं ने लाखों मरीजों को नई उम्मीद दी है। किंतु विडंबना यह है कि इन आधुनिक दवाओं की अत्यधिक कीमतें गरीब और मध्यम वर्ग के लिए इलाज को लगभग असंभव बना देती हैं। ऐसे में प्रश्न केवल चिकित्सा का नहीं, बल्कि जीवन के संवैधानिक अधिकार का बन जाता है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की महंगी दवाओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब तलब करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने उस कैंसर मरीज की मृत्यु पर गहरी चिंता व्यक्त की, जो जीवनरक्षक दवाओं को किफायती बनाने से संबंधित मामले के निर्णय की प्रतीक्षा करते-करते दुनिया से विदा हो गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह केवल दवाओं की कीमत का विवाद नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को प्राप्त जीवन और गरिमा के अधिकार का प्रश्न है। यह टिप्पणी देश की स्वास्थ्य नीति के लिए एक गंभीर संदेश है कि न्याय में देरी कई बार जीवन की हानि का कारण बन जाती है।

वास्तविकता यह है कि भारत में हर वर्ष लाखों लोग कैंसर से प्रभावित होते हैं। आधुनिक लक्षित और इम्यूनोथेरेपी दवाओं की कीमत कई बार लाखों रुपये प्रति माह तक पहुंच जाती है। अधिकांश परिवार इतनी बड़ी राशि वहन करने में सक्षम नहीं होते। परिणामस्वरूप अनेक लोग अपनी वर्षों की जमा-पूंजी खर्च कर देते हैं, कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं, जमीन-जायदाद बेच देते हैं या फिर आर्थिक तंगी के कारण बीच में ही इलाज छोड़ने को विवश हो जाते हैं। ऐसे अनेक मामलों में बीमारी से पहले आर्थिक संकट परिवार को तोड़ देता है।

दूसरी ओर यह भी सत्य है कि नई दवाओं के अनुसंधान, परीक्षण और विकास में दवा कंपनियां अरबों रुपये का निवेश करती हैं। पेटेंट व्यवस्था उन्हें सीमित अवधि तक अपने आविष्कार का आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार देती है, जिससे भविष्य के अनुसंधान को भी प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए नवाचार और अनुसंधान की रक्षा आवश्यक है। किंतु जब जीवनरक्षक दवाएं आम नागरिक की पहुंच से बाहर हो जाएं, तब सरकार का दायित्व और भी बढ़ जाता है कि वह जनहित और व्यावसायिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करे।

इस दिशा में सरकार को बहुआयामी कदम उठाने होंगे। आवश्यक कैंसर रोधी दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाना, गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देना, सरकारी अस्पतालों में इन दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का दायरा बढ़ाना तथा जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक हित में पेटेंट कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों का विवेकपूर्ण उपयोग करना समय की मांग है। साथ ही, देश में दवा अनुसंधान और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित कर आयात पर निर्भरता कम करना भी दीर्घकालिक समाधान का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका केवल कानून की व्याख्या करने वाली संस्था नहीं, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षक भी है। स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में समय पर निर्णय अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि यहां विलंब का अर्थ कई बार किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाना होता है। इसलिए ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है।

एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राष्ट्र की पहचान केवल आर्थिक विकास से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर और गंभीर बीमारी से जूझ रहे नागरिकों को कितना सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान कर पाता है। कैंसर की दवाएं कोई विलासिता की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन बचाने का अनिवार्य साधन हैं। इसलिए सरकार, दवा उद्योग, चिकित्सा समुदाय और न्यायपालिका—सभी को मिलकर ऐसा संतुलित और मानवीय समाधान विकसित करना होगा, जिसमें अनुसंधान और नवाचार भी सुरक्षित रहें तथा कोई भी मरीज केवल आर्थिक अभाव के कारण जीवनरक्षक उपचार से वंचित न रह जाए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि स्वास्थ्य को खर्च नहीं, बल्कि निवेश माना जाए। जब जीवन बचाने वाली दवाएं हर जरूरतमंद तक किफायती कीमत पर पहुंचेंगी, तभी संविधान में निहित जीवन के अधिकार की वास्तविक भावना साकार होगी और भारत एक संवेदनशील, समावेशी एवं उत्तरदायी स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में सशक्त कदम बढ़ा सकेगा।

सौरभ वार्ष्णेय
लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।

आत्मनिर्भर भारत की अंतरिक्ष युग की ऐतिहासिक उड़ान

भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली है। देश के पहले निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट 'विक्रम-1इ का सफल प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष यात्रा में एक नए युग की शुरूआत का प्रतीक है। हैदराबाद स्थित निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित इस रॉकेट ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल उड़ान भरते हुए छह पेलोड को लगभग 450 किलोमीटर ऊँची निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया।

यह उपलब्धि केवल एक तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि भारत की नवाचार क्षमता, निजी उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की सशक्त अभिव्यक्ति है।

कई दशकों तक भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम मुख्यतः भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नेतृत्व में संचालित होता रहा। चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य-एल1 जैसे मिशनों ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्तियों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया। किंतु बदलती वैश्विक परिस्थितियों और बढ़ती व्यावसायिक मांगों को देखते हुए भारत सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के द्वार खोले। इसका उद्देश्य नवाचार, निवेश और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था। विक्रम-1 की सफलता इस नीति की प्रभावशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय निजी कंपनियाँ भी विश्वस्तरीय अंतरिक्ष तकनीक विकसित करने में सक्षम हैं।

विक्रम-1 एक अत्याधुनिक, तीन-चरणीय ठोस ईंधन आधारित ऑर्बिटल रॉकेट है, जिसके अंतिम चरण में 3ष्ठ-प्रिंटेड तरल इंजन का उपयोग किया गया है। इसका ढाँचा कार्बन-कॉम्पोजिट सामग्री से निर्मित है, जिससे इसका भार कम तथा दक्षता अधिक हो जाती है। यह लगभग 350 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों को निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित करने की क्षमता रखता है।

मिशन के दौरान रॉकेट ने छह पेलोड को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में पहुँचाकर अपनी विश्वसनीयता सिद्ध की। यह सफलता भविष्य में व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के लिए भारत को एक आकर्षक वैश्विक केंद्र बना सकती है। आज वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विस्तार कर रही है। छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग के कारण कम लागत वाले प्रक्षेपण यानों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। विक्रम-1 की सफलता भारत को इस उभरते हुए बाजार में सशक्त प्रतिस्पर्धी बना सकती है।

इस उपलब्धि से अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आएँगे— भारतीय स्टार्टअप और निजी उद्योगों को नई संभावनाएँ मिलेंगी। उपग्रह प्रक्षेपण की लागत में प्रतिस्पर्धात्मक कमी आएगी। उच्च तकनीक आधारित रोजगार और अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा। विदेशी ग्राहकों के लिए भारत एक विश्वसनीय लॉन्च सेवा प्रदाता के रूप में उभरेगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति मिलेगी।

अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भूमिका अमेरिका और कुछ अन्य देशों में पहले से स्थापित रही है। भारत में विक्रम-1 की सफलता इस दिशा में निर्णायक कदम है। इससे भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जहाँ निजी क्षेत्र ने सफल ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता का प्रदर्शन किया है। यह उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की वैश्विक स्वीकार्यता को भी मजबूत करती है।

हालाँकि यह सफलता अत्यंत प्रेरणादायक है, लेकिन निजी अंतरिक्ष उद्योग के समक्ष कई चुनौतियाँ भी हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, तकनीकी विश्वसनीयता, सुरक्षा मानकों का पालन, निवेश की निरंतर उपलब्धता तथा अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों का विश्वास बनाए रखना आसान नहीं होगा। सरकार, निजी कंपनियों के बीच प्रभावी सहयोग इस क्षेत्र की दीर्घकालिक सफलता की कुंजी रहेगा। विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण केवल एक रॉकेट की उड़ान नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मविश्वास की नई उड़ान है। यह उपलब्धि दशार्ती है कि भारत अब केवल सरकारी संस्थानों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि निजी नवाचार के बल पर भी अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर है। यदि यही गति, नीति समर्थन और तकनीकी उत्कृष्टता बनी रही, तो आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र बन सकता है। विक्रम-1 ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि भारत का भविष्य केवल धरती तक सीमित नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की असीम संभावनाओं तक विस्तृत है।

सौरभ वार्ष्णेय
लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।

आलेख

संसद का मानसून सत्र : लोकतंत्र का महायुद्ध या राष्ट्रीय सहमति का महापर्व ?

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संसद है ।संविधान निमार्ताओं ने संसद को केवल कानून बनाने की संस्था नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संवाद, जनाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच के रूप में स्थापित किया ।संसद की गरिमा केवल सत्ता पक्ष के बहुमत से नहीं,बल्कि एक सशक्त,जागरूक और उत्तरदायी विपक्ष से भी निर्मित होती है ।लोकतंत्र का सौंदर्य इसी संतुलन में निहित है ।सरकार जनादेश का प्रतिनिधित्व करती है,जबकि विपक्ष जनमत की निगरानी करता है ।दोनों की सक्रिय और रचनात्मक भूमिका ही संसदीय लोकतंत्र को जीवंत बनाती है ।इसी लोकतांत्रिक परंपरा को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक संसदीय सत्र से पूर्व केन्द्र सरकार सर्वदलीय बैठक आयोजित करती है ।यद्यपि यह संविधान द्वारा अनिवार्य नहीं है, फिर भी दशकों से विकसित यह संसदीय परम्परा सरकार और विपक्ष के बीच संवाद का सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम रही है ।इस बैठक में आगामी सत्र की कार्ययोजना,विधायी प्राथमिकताओं,जनहित से जुड़े मुद्दों तथा सदन को व्यवस्थित और सुचारु रूप से चलाने पर विचार-विमर्श किया जाता है। लोकतंत्र में संवाद की यह परम्परा ही राजनीतिक मतभेदों को संवैधानिक मयार्दाओं के भीतर बनाए रखने का आधार बनती है ।20 जुलाई से प्रारम्भ हुए संसद के मानसून सत्र की शुरूआत इस बार सहमति के वातावरण में नहीं,बल्कि तीखे राजनीतिक मतभेदों के साथ हुई है ।सत्र से पूर्व आयोजित सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी,तृणमूल कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन के कई दलों ने उन सांसदों को आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति जताई,जिन्होंने अपनी मूल राजनीतिक पार्टी से अलग होने की घोषणा की है अथवा जिनकी स्थिति दल-बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अभी लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष विचाराधीन है ।विपक्ष ने इसे संसदीय मयार्दाओं के विपरीत बताते हुए बैठक का बहिष्कार किया। सरकार का पक्ष है कि निमंत्रण संसदीय अभिलेखों और उपलब्ध आधिकारिक स्थिति के आधार पर भेजे गए हैं तथा इसमें किसी प्रकार की प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है ।यह विवाद केवल एक बैठक तक सीमित नहीं है ।इसके पीछे भारतीय राजनीति में लगातार बढ़ता अविश्वास,दल -बदल की घटनाएँ, गठबंधनों का विघटन,राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर उठ रहे प्रश्न भी जुड़े हैं ।विपक्ष का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल विपक्ष को कमजोर करने की दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीति पर कार्य कर रहा है ।सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहती है कि लोकतंत्र में प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को कानून के दायरे में राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार है तथा दल- बदल से जुड़े मामलों का अंतिम निर्णय संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार संबंधित अध्यक्ष अथवा सभापति ही करते हैं ।इस बार मानसून सत्र का महत्त्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि सरकार अनेक महत्त्वपूर्ण विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने अथवा पारित कराने की तैयारी में है ।संसद की उपलब्ध कार्यसूची और सरकारी संकेतों के अनुसार आयकर(संशोधन) विधेयक,सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विकास(संशोधन)विधेयक, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन)विधेयक,सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने संबंधी विधेयक, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक तथा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम में संशोधन जैसे विषय सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। हालाँकि संसद की कार्यसूची गतिशील होती है और कार्यमंत्रणा समिति अथवा सरकार के निर्णय के अनुसार इसमें परिवर्तन,नए विधेयकों का समावेश अथवा प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण भी संभव है ।सरकार का दावा है कि इन विधेयकों का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार,न्यायिक दक्षता,कर व्यवस्था का सरलीकरण,निवेश को प्रोत्साहन, सुशासन तथा पारदर्शिता को और अधिक सुदृढ़ करना है ।सरकार का यह भी कहना है कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विधायी सुधारों की गति बनाए रखना समय की आवश्यकता है ।यही कारण है कि मानसून सत्र को सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के सबसे महत्त्वपूर्ण विधायी सत्रों में से एक मान रही है ।दूसरी ओर राजनीतिक विमर्श का सबसे संवेदनशील विषय संविधान संशोधन,परिसीमन तथा महिला आरक्षण का प्रभावी क्रियान्वयन बना हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पारित हो चुका है,किन्तु उसका वास्तविक क्रियान्वयन नई जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही संभव है ।विपक्ष का आरोप है कि महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने के बजाय भविष्य की प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है। सरकार का कहना है कि संविधान के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत परिसीमन के बिना आरक्षण लागू करना संभव नहीं है ।स्पष्ट है कि यह विषय राजनीतिक बहस के साथ-साथ संवैधानिक व्याख्या का भी प्रश्न बन चुका है ।परिसीमन आने वाले वर्षों की भारतीय राजनीति का सबसे महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विषय बनता दिखाई दे रहा है। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व में परिवर्तन की संभावना है ।दक्षिण भारत के अनेक राज्यों और क्षेत्रीय दलों ने पहले ही आशंका व्यक्त की है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त करने वाले राज्यों को प्रतिनिधित्व के स्तर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है ।दूसरी ओर उत्तर भारत के राज्य समान जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देते हैं ।इसलिए परिसीमन केवल चुनावी गणित का विषय नहीं, बल्कि संघीय ढाँचे,क्षेत्रीय संतुलन और राष्ट्रीय राजनीतिक संरचना से जुड़ा संवेदनशील प्रश्न बन गया है ।मानसून सत्र में विपक्ष की रणनीति भी लगभग स्पष्ट दिखाई दे रही है ।विपक्ष संसद के भीतर सरकार को भ्रष्टाचार,बेरोजगारी,महँगाई,कृषि संकट,राज्यों के अधिकार,संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता,जाँच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग,दल-बदल, सामाजिक न्याय तथा महिला आरक्षण के क्रियान्वयन जैसे विषयों पर घेरने की तैयारी में है। इसके अतिरिक्त लद्दाख को संवैधानिक संरक्षण,छठी अनुसूची के प्रावधानों तथा पर्यावरणीय संरक्षण की माँग को लेकर सोनम वांगचुक द्वारा चलाए गए आंदोलन को भी विपक्ष राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाने का प्रयास करेगा ।सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास, पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय जनप्रतिनिधित्व अब केवल क्षेत्रीय मुद्दे नहीं,बल्कि राष्ट्रीय नीति के अभिन्न अंग बन चुके हैं ।भ्रष्टाचार का प्रश्न भी इस सत्र में प्रमुखता से उठ सकता है ।विपक्ष विभिन्न सरकारी निर्णयों, सार्वजनिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा राजनीतिक जवाबदेही को लेकर सरकार से प्रश्न पूछने की तैयारी में है ।वहीं सरकार डिजिटल भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण,सरकारी खरीद की ई-प्रणाली, जीएसटी, डिजिटल प्रशासन तथा तकनीक आधारित पारदर्शिता को भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत कर रही है। स्वाभाविक है कि इस विषय पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद केवल बहुमत का मंच नहीं होती। संविधान के अनुच्छेद107 से 111 तक विधेयकों की संसदीय प्रक्रिया का उल्लेख है,जबकि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है ।इसी प्रकार दसवीं अनुसूची दल-बदल विरोधी कानून का आधार है ।इन प्रावधानों का मूल उद्देश्य लोकतांत्रिक स्थिरता,जनादेश की रक्षा और संसदीय मयार्दाओं को सुरक्षित रखना है ।यदि राजनीतिक विवादों का समाधान इन्हीं संवैधानिक व्यवस्थाओं के माध्यम से होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है ; किन्तु यदि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास बढ़ता है,तो उसका प्रभाव लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दूरगामी होता है ।यह भी स्मरण रखना होगा कि संसद का दायित्व केवल विधेयक पारित करना नहीं है ।संसद सरकार से प्रश्न पूछती है,नीतियों की समीक्षा करती है,सार्वजनिक धन के उपयोग पर निगरानी रखती है तथा जनता की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय नीति में स्थान देती है ।इसलिए संसद का प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा राष्ट्र की अमूल्य लोकतांत्रिक पूँजी है। यदि पूरा सत्र केवल हंगामे, नारेबाजी और स्थगन की भेंट चढ़ जाता है,तो सबसे बड़ा नुकसान जनता के विश्वास और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को होता है ।आज भारत महँगाई,रोजगार, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं,कृत्रिम बुद्धिमत्ता,जलवायु परिवर्तन,कृषि सुधार,राष्ट्रीय सुरक्षा,साइबर सुरक्षा,शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक समरसता जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन विषयों पर गंभीर संसदीय विमर्श की अपेक्षा केवल विपक्ष या सरकार की नहीं,बल्कि पूरे राष्ट्र की है। जनता चाहती है कि संसद राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मंच अवश्य बने,किन्तु राष्ट्रीय समाधान का केन्द्र भी बनी रहे ।20 जुलाई से प्रारम्भ हुआ यह मानसून सत्र केवल सरकार के विधायी एजेंडे अथवा विपक्ष के राजनीतिक प्रतिरोध तक सीमित नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता,संसदीय परम्पराओं और संवैधानिक मूल्यों की भी परीक्षा है ।सरकार के सामने चुनौती है कि वह अपने बहुमत का उपयोग संवाद, सहमति और संवैधानिक मयार्दाओं के साथ करे,जबकि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह तथ्य,तर्क और जनहित के आधार पर अपनी भूमिका निभाए ।लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति बहुमत नहीं,बल्कि संविधान के प्रति सामूहिक आस्था है ।अंततः संसद किसी एक दल,गठबंधन या सरकार की नहीं,बल्कि भारत की जनता की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है। मतभेद लोकतंत्र का स्वाभाविक गुण हैं,परन्तु संवाद उसका प्राण है ।यदि यह मानसून सत्र राजनीतिक संघर्ष के बीच भी राष्ट्रीय सहमति का मार्ग प्रशस्त करता है,तो यह भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का नया अध्याय सिद्ध होगा ।यदि संवाद की जगह केवल टकराव ले लेता है,तो इतिहास इसे एक खोए हुए अवसर के रूप में भी दर्ज करेगा। लोकतंत्र की वास्तविक विजय सत्ता की नहीं,बल्कि संसद की गरिमा,संविधान की प्रतिष्ठा और जनविश्वास की विजय होती है।

लेखक – विनोद कुमार सिंह तकियावाला
(स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तम्भकार)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संक्षिप्त वार्ता

फतेह नगर में तड़के भीषण आग, दो एलपीजी सिलेंडर फटे

नई दिल्ली, 21 जुलाई (वेब वार्ता)। पश्चिमी दिल्ली के फतेह नगर इलाके में मंगलवार तड़के एक मकान की पार्किंग में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में दो कारें, दो स्कूटी और ग्राउंड प्लस तीन मंजिला मकान का निचला हिस्सा आ गया। घटना के दौरान दो एलपीजी सिलेंडरों में धमाके होने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि दमकल कर्मियों की तत्परता से आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, सुबह करीब 3:48 बजे फतेह नगर स्थित डी-177, जेल रोड, रणबीर बेकरी के पास एक मकान की पार्किंग में आग लगने की सूचना मिली। मामले की सूचना मिलते ही दमकल की कुल नौ गाड़ियों को मौके पर लगाया गया।

खरगे ने छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में नहीं मनाया जन्मदिन

नई दिल्ली, 21 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को अपना जन्मदिन नहीं मनाया। उन्होंने कहा कि बच्चों को दमन नहीं, न्याय चाहिए। इसलिए, आज जश्न मनाने का नहीं, जवाबदेही मांगने का दिन है। यह लोकतंत्र बहाली की मांग का दिन है। खरगे ने एक्स पर कहा कि वह पार्टी नेताओं, कार्यकताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों और उन सभी नागरिकों के आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। खरगे ने कहा कि लोगों का स्नेह उनके लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन एक दिन पहले देश ने छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और केंद्र सरकार की तरफ से एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन को कुचले जाते देखा।

लेह हवाई अड्डे पर रनवे बाधित, उड़ानें प्रभावित

नई दिल्ली, 21 जुलाई (वेब वार्ता)। लेह हवाई अड्डे पर रनवे में आई तकनीकी बाधा के कारण लेह से आने और जाने वाली उड़ानें प्रभावित हो गई हैं। आईजीआई ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। हवाई अड्डा प्रशासन के अनुसार, लेह एयरपोर्ट पर रनवे में आई रुकावट के कारण कई उड़ानों के समय में बदलाव, देरी या रद्द होने की संभावना है। एयरपोर्ट ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी उड़ान की ताजा स्थिति जानने के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें या यात्रा पर निकलने से पहले उड़ान का स्टेटस अवश्य जांच लें। एयरपोर्ट प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि हालात सामान्य होते ही उड़ान सेवाओं को सुचारू करने का प्रयास किया जाएगा।

निदेशों के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने का आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई (वेब वार्ता)। एंटरप्रेन्योर अंकीति बोस की ओर से दायर मानहानि मामले में द्वारका कोर्ट ने प्रतिवादियों को अदालत से पहले से जारी अंतरिम रोक आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि रोक आदेश का उल्लंघन हुआ है। जिला न्यायाधीश हरजोत सिंह भल्ला ने प्रतिवादी नितिन नरेश और अन्य को अदालत के निदेशों के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।

डीयू एडमिशन: यूजी में 45 हजार से अधिक छात्रों ने लिया दाखिला

नई दिल्ली, 21 जुलाई (वेब वार्ता)

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक (यूजी) दाखिले की प्रथम आवंटन प्रक्रिया के तहत प्रवेश का क्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 45,316 अभ्यर्थी अपनी आवंटित सीट स्वीकार कर प्रवेश की पुष्टि कर चुके हैं। यह कुल सीट आवंटन का 48.71 प्रतिशत है। जिन विद्यार्थियों ने अपनी सीट सुरक्षित कर ली है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 रात 11:59 बजे निर्धारित की गई है। तय समय तक फीस जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया स्वतः निरस्त मानी जा सकती है और उनकी सीट अगले चरण की काउंसलिंग में उपलब्ध करा दी जाएगी। विश्वविद्यालय ने सभी चयनित विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की तकनीकी परेशानी से बचने के लिए समय रहते शुल्क जमा कर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लें।

डीयू बीकॉम प्रवेश में किरोड़ीमल कॉलेज सबसे आगे

दिल्ली विश्वविद्यालय ने कॉमन सीट

एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस) के तहत स्नातक प्रवेश के पहले चरण की आवंटन सूची के साथ बीकॉम और बीकॉम (ऑनर्स) की न्यूनतम प्रवेश अंक भी जारी कर दिए हैं। सामान्य वर्ग में बीकॉम के लिए सबसे अधिक कटऑफ किरोड़ीमल कॉलेज में 889.8221 अंक रही। इसके बाद रामजस कॉलेज (884.0061) और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज (876.9263) रहे। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज (869.403), श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स (844.4022), दौलतराम कॉलेज (834.4386), आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज (826.3381) और जीसस एंड मैरी कॉलेज (823.3662) का स्थान रहा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वर्गों में भी प्रमुख कॉलेजों के लिए प्रवेश अंक अपेक्षाकृत ऊंचे दर्ज किए गए। वहीं, पहले चरण में बीकॉम के लिए सबसे कम प्रवेश अंक श्याम लाल इवनिंग कॉलेज में 608.9826 रहे।

डीयू बीटेक तीसरे चरण का सीट आवंटन जारी

डीयू ने बीटेक प्रवेश 2026 के तीसरे चरण का सीट आवंटन परिणाम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग प्रवेश वेबसाइट पर जेईई आवेदन संख्या और पासवर्ड की मदद से अपना आवंटन देख सकते हैं। तीसरे चरण में सीट पाने वाले छात्रों को 21 जुलाई तक सीट स्वीकार करनी होगी। इसके बाद 22 जुलाई को ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन होगा, जबकि प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को समयसीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

डीयू में 28 से दो कंट्रोल रूम होंगे सक्रिय

डीयू ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 शुरू होने से पहले परिसर में सुरक्षा और अनुशासन को लेकर विशेष तैयारियां पूरी कर ली हैं। नए विद्यार्थियों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए 28 जुलाई से 7 अगस्त तक उत्तर और दक्षिण परिसर में दो संयुक्त कंट्रोल रूम संचालित किए जाएंगे। यहां छात्र-छात्राएं रैगिंग, छेड़छाड़ या अन्य शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। सभी कॉलेजों, विभागों और हॉस्टलों में एंटी-रैगिंग एवं अनुशासन समितियां तथा विजिलेंस स्क्वॉड सक्रिय रहेंगे। जहां आवश्यकता होगी, वहां एनसीसी और एनएसएस स्वयंसेवकों का भी सहयोग लिया जाएगा। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों और छात्रावासों को बाहरी लोगों के प्रवेश पर सख्ती से नियंत्रण रखने तथा एंटी-रैगिंग नियमों को प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक कॉलेज के बाहर पुलिस पिकेट तैनात रहेगी। किसी भी अनुशासनहीन घटना पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

पीजी सत्यापन और शपथ-पत्र अनिवार्य

बैठक में छात्रों को पीजी या किराये के आवास में रहने से पहले स्थानीय पुलिस से सत्यापन कराने की सलाह दी गई। दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों के आसपास नियमित गश्त बढ़ाने का भरोसा दिया। वहीं, सभी नए विद्यार्थियों और छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए एंटी-रैगिंग पोर्टल पर ऑनलाइन अंडरटेकिंग जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। विश्वविद्यालय परिसर में जागरूकता बढ़ाने के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एंटी-रैगिंग पोस्टर व बैनर लगाए जाएंगे।

प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा ने केजरीवाल की निंदा की

नई दिल्ली, 21 जुलाई (वेब वार्ता)

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी (आआपा) के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आतंकवादी कहे जाने की कड़ी निंदा की।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति जारी कर केजरीवाल के बयान की निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर दिया गया यह बयान न केवल गलत है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान पर सीधा प्रहार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और आतंकी ढांचे को तोड़ने का काम हुआ।

मल्होत्रा ने कहा कि आज पूरा विश्व जहां भारत को आतंक के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज के रूप में देखता है, तो वही विपक्ष में बैठे लोगों को यह बात हजम नही हो रही है। इसलिए वह लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर राजनीति कर रहे है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कैसे प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते है। उन्होंने कहा कि यह सब केजरीवाल की राजनीतिक हताशा, नैतिक पतन और दिल्ली की सत्ता खोने की बौखलाहट को दशार्ता है। मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 10 साल दिए। लेकिन आआपा ने दिल्ली में भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नही किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल से तुरंत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की।

टाउन वेंडिंग समिति चुनाव की रणनीति पर राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ की बैठक

नई दिल्ली, 21 जुलाई (वेब वार्ता)। आगामी टाउन वेंडिंग समिति चुनावों की तैयारियों और कार्ययोजना को लेकर राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को करोल बाग स्थित होटल जेनिफर इन में आयोजित की गई। बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लेकर चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से संपन्न कराने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक में निर्णय लिया गया कि महासंघ आगामी चुनावों में अधिक से अधिक पात्र रेहड़ी, पटरी और ठेला व्यवसायियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगा। इसके साथ ही सभी राज्य और जिला इकाइयों को स्थानीय स्तर पर बैठकें आयोजित करने, जागरूकता अभियान चलाने तथा सदस्यता अभियान को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक पांडेय ने कहा कि टाउन वेंडिंग समिति का गठन स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम, 2014 के प्रभावी क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण आधार है।

उन्होंने कहा कि समिति में वास्तविक और सक्रिय स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधियों का चयन होना आवश्यक है, ताकि रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों की समस्याओं का प्रभावी समाधान हो सके और उनके अधिकारों की समुचित रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक निगम ने कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता होती है अथवा पात्र स्ट्रीट वेंडरों के अधिकारों का हनन किया जाता है, तो महासंघ लोकतांत्रिक और संवैधानिक माध्यमों से उसका विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष संगठन अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। बैठक के अंत में सभी पदाधिकारियों और कार्यकताओं ने आगामी टाउन वेंडिंग समिति चुनावों में संगठन की सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाने का संकल्प लिया। साथ ही देशभर के स्ट्रीट वेंडरों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लेने और अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की गई।

बैठक में महेश्वर बल, सतीश गौड़, बबीता सिंह, रंजन कुमार, विजय सिंह, अधिवक्ता गोपाल सिंह, अधिवक्ता शशांक श्रीवास्तव, अजय सिंह बॉबी, डॉ. गौरव प्रकाश, डॉ. अनिल कुमार तथा हरिशंकर सिन्हा सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

दिल्ली नगर निगम जोनों के नाम राजस्व जिलों के अनुरूप किए गए

नई दिल्ली, 21 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, स्पष्ट और जनसुविधा के अनुरूप बनाने के लिए निगम जोन के नाम राजस्व जिलों के अनुरूप किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की चौदहवीं अनुसूची में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक स्पष्ट, सुगम और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की चौदहवीं अनुसूची में किया गया संशोधन दिल्ली के राजस्व प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक होगा। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि शासन व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए। प्रशासनिक क्षेत्रों के नामकरण में एकरूपता से विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा, योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा और दिल्ली के नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ अधिक सुगमता से मिल सकेगा।

दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने 25 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 39 उप-मंडल/तहसील और 13 जिले बनाए थे। इन क्षेत्रों को दिल्ली नगर निगम के 12 जोनों, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली छावनी क्षेत्र के अनुरूप रखा गया है। प्रशासनिक दक्षता और जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए अब दिल्ली नगर निगम के मौजूदा जोनों के नामों को नए राजस्व जिला नामकरण के साथ औपचारिक रूप से एकरूप किया गया है। इसके तहत दिल्ली नगर निगम के 12 जोन अब बाहरी उत्तर, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, मध्य उत्तर, पुरानी दिल्ली, मध्य, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण, पूर्व और उत्तर-पूर्व के नाम से सूचीबद्ध हैं।

पुलिस कार्रवाई के विरोध में केवाईएस ने किया 'काला दिवस' का आह्वान

क्रांतिकारी युवा संगठन ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में देशभर में 'काला दिवस' मनाने का आह्वान किया है।

नई दिल्ली, वेब वार्ता

संगठन का कहना है कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर चल रहे आंदोलन के समर्थन में विभिन्न स्थानों पर शांतिपूर्ण विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

संगठन के अनुसार संसद मार्च में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और अन्य नागरिक शामिल हुए थे। संगठन ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर बढ़ने से रोका गया तथा उनके साथ बल प्रयोग किया गया। संगठन ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के विपरीत बताया। क्रांतिकारी युवा संगठन ने कहा कि आंदोलनकारियों की मांगों पर सरकार को संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए। संगठन का दावा है कि जब तक उनकी मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। वहीं, पुलिस और सरकार की ओर से इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

लोकहा बाजार के लिए विशेष रेलगाड़ी की अवधि बढ़ाई

नई दिल्ली, 21 जुलाई (वेब वार्ता)। यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार टर्मिनल से लोकहा बाजार के बीच चलाई जा रही विशेष रेलगाड़ी की सेवा अवधि को 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गाड़ी संख्या 04014 आनंद विहार टर्मिनल से प्रतिदिन (15 अगस्त तक) लोकहा बाजार के लिए चलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 04013 लोकहा बाजार से प्रतिदिन (16 अगस्त तक) चलकर आनंद विहार टर्मिनल आएगी।

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश, तीन दिन तक चेतावनी

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। करीब दो सप्ताह के विराम के बाद राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। दिनभर बादलों की आवाजाही के बीच कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया।

मौसम विभाग के अनुसार सुबह 8:30 बजे तक 7.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिनभर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए पीली चेतावनी जारी की है। इस दौरान कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा तथा कुछ इलाकों में भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है। लोगों को जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उधर, राजधानी की वायु गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज किया गया। मंगलवार सुबह 10 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 88 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया। विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक वायु गुणवत्ता में अधिक बदलाव की संभावना नहीं है।

आतंकी वित्तपोषण मामले में जमानत पर रोक से इनकार

नई दिल्ली, 21 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 के कथित आतंकी वित्तपोषण मामले में खुर्रम परवेज और इरफान मेराज को निचली अदालत से मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने सख्त शर्तों के साथ दी गई जमानत को बरकरार रखा।

एनसीआर से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के यात्रियों को हुई परेशानी

गाजियाबाद-नई दिल्ली रेलखंड पर मालगाड़ी बेपटरी, 53 ट्रेनें प्रभावित

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। उत्तर रेलवे के गाजियाबाद-नई दिल्ली रेलखंड पर मंगलवार को साहिबाबाद के पास एक मालगाड़ी के छह डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दुर्घटना से रेलवे का परिचालन दिनभर बुरी तरह प्रभावित रहा। विभिन्न मार्गों की करीब 53 ट्रेनों के संचालन में बदलाव करना पड़ा, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी हुई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

कई राज्यों के यात्री प्रभावित

हादसे का असर केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं रहा। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब और झारखंड जाने-आने वाले यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रभावित प्रमुख ट्रेनों में गोल्डन टेंपल मेल, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस, नंदा देवी एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति, श्रमशक्ति एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, लखनऊ मेल, प्रयागराज एक्सप्रेस, तेजस राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस शामिल रहीं। इन ट्रेनों के यात्रियों को मार्ग परिवर्तन, देरी और लंबी प्रतीक्षा का सामना करना पड़ा। जयनगर-नई दिल्ली एक्सप्रेस और सहारनपुर-दिल्ली पैसेंजर का मार्ग भी बदला गया, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों की यात्रा अवधि बढ़ गई।

दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक, अपर मंडल रेल प्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेलवे की इंजीनियरिंग, परिचालन और तकनीकी टीमें युद्धस्तर पर राहत एवं बहाली कार्य में जुट गईं। पटरी से उतरे डिब्बों को हटाने और क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत का काम पूरे दिन चला। रेलवे ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। उत्तर रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (एनटीईएस) और रेलवे हेल्पलाइन 139 के माध्यम से अवश्य जांच लें। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित रेलखंड पर बहाली का कार्य लगातार जारी है। ट्रैक पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही नियमित रेल सेवाएं सामान्य रूप से बहाल की जाएंगी।

ट्रेनों के संचालन पर व्यापक असर

रेलवे के अनुसार, दुर्घटना के कारण 16 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। 24 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया। पांच ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त किया गया और आठ ट्रेनों को नियंत्रित कर चलाया गया। इस हादसे के कारण गाजियाबाद-नई दिल्ली, नई दिल्ली-गाजियाबाद, दिल्ली-साहिबाबाद और साहिबाबाद-दिल्ली के बीच चलने वाली कई ईएमयू लोकल ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं। इससे दिल्ली-एनसीआर के हजारों दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और व्यापारिक यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा या सड़क मार्ग से सफर के लिए अतिरिक्त खर्च और समय देना पड़ा।

वैकल्पिक मार्गों से परिचालन

रेलवे ने कई ट्रेनों का मार्ग बदलकर परिचालन जारी रखा। कुछ ट्रेनों को दिल्ली-नई दिल्ली के बजाय वैकल्पिक रेलमार्ग से चलाया गया। लंबी दूरी की कुछ ट्रेनों को टुंडला, आगरा कैंट और पलवल होकर गंतव्य तक भेजा गया। कई ट्रेनों को रास्ते में रोककर नियंत्रित गति से चलाया गया, जिससे उनके निर्धारित समय में काफी देरी हुई।

भाजपा के पास ही रहेगी स्थायी समिति की कमान

अध्यक्ष पद पर सत्या शर्मा की राह आसान

नई दिल्ली, 21 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली नगर निगम की सबसे प्रभावशाली वैधानिक समिति मानी जाने वाली स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त लगभग तय मानी जा रही है। मंगलवार को अध्यक्ष पद के लिए सत्या शर्मा तथा उपाध्यक्ष पद के लिए सत्यपाल सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मौजूदा संख्या बल के आधार पर दोनों उम्मीदवारों की जीत लगभग निश्चित मानी जा रही है।

दिल्ली नगर निगम सचिव अनिल कुमार यादव के समक्ष दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर महापौर प्रवेश वाही, नेता सदन जय भगवान यादव, उपमहापौर डॉ. मोनिका पंत तथा वरिष्ठ पार्षद मुकेश गोयल भी उपस्थित रहे। स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव 27 जुलाई को निर्धारित है।

स्थायी समिति के संख्या बल पर दृष्टि डालें तो भारतीय जनता पार्टी के कुल 12 सदस्य हैं। इनमें सदन से 4 तथा वार्ड समितियों से चुने गए 8 सदस्य शामिल हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के पास कुल 6 सदस्य हैं, जिनमें सदन से 2 और वार्ड समितियों से 4 सदस्य हैं। अब तक आम आदमी पार्टी की ओर से किसी उम्मीदवार का नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दोनों पदों पर निर्विरोध अथवा सहज जीत दर्ज करना लगभग तय माना जा रहा है। स्थायी समिति दिल्ली नगर निगम की सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक समिति मानी जाती है। निगम की वित्तीय स्वीकृतियों, विकास योजनाओं, विभिन्न परियोजनाओं और नीतिगत प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय इसी समिति के माध्यम से लिया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन के बाद अगस्त माह में समिति की पहली बैठक आयोजित होने की संभावना है।

पहली बैठक में नगर के अपशिष्ट प्रबंधन, कूड़ा निस्तारण, जैव खनन प्रक्रिया, पार्किंग व्यवस्था तथा विभिन्न नियमों में संशोधन से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

संक्षिप्त वार्ता

भगवान श्रीराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ललितपुर। सोशल मीडिया पर मयार्दा पुरुषोतम भगवान श्रीराम के संबंध में आपत्तिजनक एवं धार्मिक भावनाएं आहत कर करने वाला वीडियो पोस्ट करने के मामले में जखौरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में कानून के प्रति सख्त रुख का स्पष्ट संदेश गया है। बजरंग सेना के सदस्य आशीष रावत पुत्र जगदीश प्रसाद रावत निवासी मकरीपुर (नाराहट) की लिखित शिकायत के आधार पर थाना जखौरा में मु.अ.सं. 196/26 के तहत धारा 299 बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार बैस के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रविन्द्र राजपूत (21 वर्ष) निवासी ग्राम बरोदास्वामी, थाना जखौरा को गिरफ्तार कर लिया।

नघेटा पूर्वी की बदहाल गलियों को लेकर सपा नेता ने उठाए सवाल

वेब वार्ता, हरदोई

नगर के मोहल्ला नघेटा पूर्वी की जर्जर गलियों और जलभराव की समस्या को लेकर समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव एवं हरदोई नगर पालिका अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी रामज्ञान गुप्ता ने नगर पालिका प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर में विकास कार्य अपेक्षित स्तर पर नहीं हो रहे हैं, जिससे लोगों को रोजमर्रा की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रामज्ञान गुप्ता ने कहा कि नघेटा पूर्वी सहित नगर के कई मोहल्लों की गलियां खस्ताहाल हैं। बारिश होने पर जलभराव की स्थिति बन जाती है, जिससे पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका विकास के दावे तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अलग दिखाई देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर विकास के लिए आने वाली धनराशि का सही उपयोग नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि जनता जानना चाहती है कि विकास कार्यों के लिए मिलने वाला बजट किन कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने नगर पालिका में पारदर्शिता लाने और विकास कार्यों की समीक्षा कराने की मांग की।

लंबित मुकदमों का जल्द निस्तारण करें, दोषसिद्धि दर बढ़ाएं: डीएम

वेब वार्ता, हरदोई

जिलाधिकारी अनुनय झा ने सोमवार को स्वामी विवेकानंद सभागार में अभियोजन कार्यों की समीक्षा करते हुए न्यायालयों में लंबित पुराने मुकदमों का शीघ्र और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों में अभियोजन, पुलिस और संबंधित विभाग बेहतर समन्वय के साथ काम करें ताकि दोषसिद्धि दर में वृद्धि हो सके। समीक्षा बैठक में एससी/एसटी एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों की प्रगति पर चर्चा की गई। डीएम ने इन मामलों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

एक सचिव के भरोसे कछौना ब्लॉक की खाद व्यवस्था

आधी समितियां बंद; किसानों में नाराजगी

वेबवार्ता/हरदोई

शेयर के रूप में जमा लाखों रूपये फंसे हुये हैं

किसानों ने यह भी कहा कि जागरूकता की कमी के कारण कई किसान आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव मानव स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता पर पड़ता है। इसके अलावा हरदोई किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (एफपीओ) के निष्क्रिय होने पर भी किसानों ने चिंता जताई और आरोप लगाया कि इसमें किसानों के शेयर के रूप में जमा लाखों रुपये फंसे हुए हैं।

खरीफ सीजन के बीच कछौना विकासखंड में किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। धान की रोपाई, मक्का, उड़द, ज्वार और बाजरा की बुवाई के दौरान साधन सहकारी समितियों, उपभोक्ता संघ और पीसीएफ केंद्रों पर यूरिया, डीएपी और एनपीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने से किसान खुले बाजार से अधिक कीमत पर खाद खरीदने को मजबूर हैं। किसानों का आरोप है कि 266 मूल्य की यूरिया उन्हें बाजार में करीब 400 तक में मिल रही है।

क्षेत्र के किसानों का कहना है कि विकासखंड की चार क्रियाशील साधन सहकारी समितियां—कछौना-पतसेनी, बालामऊ, पुरवा (मतुआ) और गौसगंज—में से केवल बालामऊ में नियमित सचिव तैनात हैं, जबकि शेष समितियों का संचालन एक ही सचिव के भरोसे किया जा रहा है। समितियों के संचालन का कोई निर्धारित रोस्टर न होने से किसानों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और समय पर खाद नहीं मिल पा रही है।

किसानों ने आरोप लगाया कि महरी, हथौड़ा, राज्य पहांवा, खजोहना, सुठेना और कमीपुर साधन सहकारी समितियां लंबे समय से बंद पड़ी हैं। इन समितियों को पुनः संचालित करने के लिए सदस्यता अभियान चलाकर किसानों से लाखों रुपये सदस्यता शुल्क के रूप में जमा कराए गए, लेकिन अब तक संचालन शुरू नहीं हो सका।

स्टेशन पास रेलवे क्रॉसिंग के निकट स्थित पीसीएफ केंद्र भी कई वर्षों से बंद होने के कारण किसानों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों का आरोप है कि संडीला औद्योगिक क्षेत्र में फैक्टरियों को बड़े पैमाने पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं हो रही।

क्षेत्रीय विकास जन आंदोलन के संयोजक रामखेलावन कनौजिया, इंद्रजीत यादव, प्रेम यादव, ऋषि सिंह, कमलेश वर्मा कंथा, उजागर लाल सहित सैकड़ों किसानों ने शासन और प्रशासन को पत्र भेजकर सभी साधन सहकारी समितियों का नियमित संचालन सुनिश्चित करने, बंद पीसीएफ केंद्र को चालू कराने तथा किसानों को निर्धारित मूल्य पर समय से खाद उपलब्ध कराने की मांग की है।

नघेटा पूर्वी की बदहाल गलियों को लेकर सपा नेता ने उठाए सवाल

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। नगर के मोहल्ला नघेटा पूर्वी की जर्जर गलियों और जलभराव की समस्या को लेकर समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव एवं हरदोई नगर पालिका अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी रामज्ञान गुप्ता ने नगर पालिका प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर में विकास कार्य अपेक्षित स्तर पर नहीं हो रहे हैं, जिससे लोगों को रोजमर्रा की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

रामज्ञान गुप्ता ने कहा कि नघेटा पूर्वी सहित नगर के कई मोहल्लों की गलियां खस्ताहाल हैं। बारिश होने पर जलभराव की स्थिति बन जाती है, जिससे पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका विकास के दावे तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अलग दिखाई देती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि नगर विकास के लिए आने वाली धनराशि का सही उपयोग नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि जनता जानना चाहती है कि विकास कार्यों के लिए मिलने वाला बजट किन कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने नगर पालिका में पारदर्शिता लाने और विकास कार्यों की समीक्षा कराने की मांग की। सपा नेता ने कहा कि थोड़ी देर की बारिश में ही शहर के कई हिस्सों में पानी भर जाता है। उन्होंने दावा किया कि कई स्थानों के साथ कुछ सरकारी आवास भी जलभराव से प्रभावित होते हैं। उनके अनुसार यह नगर की जल निकासी व्यवस्था और विकास कार्यों की स्थिति को दर्शाता है। रामज्ञान गुप्ता ने प्रशासन से प्रभावित मोहल्लों का निरीक्षण कराकर सड़क, नाली और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की।

3 अगस्त से शुरू होगा उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र

लखनऊ, 21 जुलाई (वेब वार्ता)। योगी सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को 3 अगस्त से आहूत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक तथा अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे। लोक भवन स्थित मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आगामी सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों का होगा। इसमें अनुपूरक अनुदानों की मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी और आवश्यक विधेयकों पर भी विचार किया जाएगा।

मदनपुर पुलिस की त्वरित कार्यवाही से हुई मोबाइल की बरामदगी

12,500 रुपये का फोन बरामद कर मालिक को किया सुपुर्द

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ललितपुर। थाना मदनपुर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही और तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए एक खोया हुआ मोबाइल फोन बरामद कर उसके वास्तविक स्वामी को सौंप दिया। करीब 12,500 रुपये कीमत का मोबाइल वापस मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और उसने एसपी सहित थाना मदनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया। एसपी संजीव कुमार बाजपेई के निर्देशन, एएसपी कालू सिंह एवं सीओ मड़ावरा आलोक कुमार अग्रहरि के पर्यवेक्षण में थाना मदनपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार जनसुनवाई एवं पोर्टल के माध्यम से प्राप्त खोए मोबाइल की शिकायत पर नियमानुसार गुमशुदगी दर्ज की गई। इसके बाद थाना मदनपुर पुलिस टीम ने पीड़ित द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का परीक्षण कर भारत सरकार के सीईआईआर पोर्टल पर मोबाइल की जानकारी अपलोड की। विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त तकनीकी डेटा और विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने खोया हुआ मोबाइल बरामद कर उसके वास्तविक स्वामी को नियमानुसार सुपुर्द कर दिया। मोबाइल वापस मिलने पर पीड़ित ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेई तथा थाना मदनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया। इस कार्रवाई को थानाध्यक्ष राजपाल सिंह के नेतृत्व में थाना मदनपुर पुलिस टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

मेहनत और अनुशासन की मिसाल सैयद बदीउद्दीन इंटर कालेज में जेईई नीट विजेताओं का स्वागत

वेब वार्ता, कमर खान

पचपेड़वा / बलरामपुर। सैयद बदीउद्दीन इंटर कॉलेज विशुनपुर टनटनवा, पचपेड़वा में मंगलवार को भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जेईई और नीट जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यालय का नाम रोशन करने वाले होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनकी उपलब्धियों को सराहा गया।

समारोह में भरत लाल पाल को जेईई में 18823वीं रैंक प्राप्त करने पर विशेष सम्मान दिया गया जबकि ईशा श्रीवास्तव को नीट में 10971वीं रैंक पर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। वहीं मोहम्मद जहीर को 10+2 की परीक्षाओं में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बेहतरीन अंक प्राप्त कर जनपद का नाम रौशन करने हेतु सम्मानित किया गया। तीनों प्रतिभाशाली छात्रों को चांदी का मेडल पहनाकर स्लेटिफाई कर सम्मानित किया गया। भरत लाल पाल व ईशा श्रीवास्तव दोनों ने इसी विद्यालय से इंटर तक की पढ़ाई पूरी की है।

मुख्य अतिथि मदन लाल जायसवाल अध्यक्ष महाराणा जन

जातीय सेवा संस्थान, ने अपने सम्बोधन में कहा कि मेहनत, लगन और अनुशासन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। हमारे विद्यालय के बच्चों ने जेईई, नीट जैसी कठिन परीक्षाओं में सफलता पाकर पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। मैं सभी प्रतिभाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि ये आगे चलकर देश और समाज का नाम और ऊंचा करेंगे।

कार्यक्रम में प्रधानाचार्य मोहम्मद अबुल लैस, उप प्रधानाचार्य मोहम्मद इरफान खान के साथ अध्यापक मो नईम खां, मो इमरान खां, जमाल अहमद खां, अब्दुल हमीद, दुर्गेश चौधरी, महमूदुल हसन, नील मणि त्रिपाठी, मो फैजान, सलाउद्दीन खां, आलम मोहम्मद, अहमद फरुल, पुनीत मौर्य, मजीद, गुड्डू श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में अभिभावक और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम शिक्षा के प्रति प्रेरणा बढ़ाते हैं तथा अन्य विद्यार्थियों में भी मेहनत करने की भावना जागृत करते हैं।

समारोह के अंत में विजेताओं का स्वागत किया गया और उन्हें आगे की पढ़ाई एवं करियर के लिए शुभकामनाएँ दी गई। विद्यालय प्रशासन ने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की योजना जताई जिससे छात्र छात्राओं को सार्वजनिक मंच पर प्रोत्साहन मिल सके।

ऑपरेशन कवचः कानपुर में अनधिकृत वाहनों पर शिकंजा

22 का चालान, 4 वाहन सीज

वेब वार्ता, हरी शंकर शर्मा

कानपुर। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और अनधिकृत रूप से चल रहे वाहनों पर कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में दो दिवसीय विशेष ह्यऑपरेशन कवचह्ल चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कानपुर नगर में परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 22 अवैध संचालित वाहनों का चालान किया, जबकि नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वाले 4 वाहनों को सीज कर बंद कर दिया।

इस विशेष अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए परिवहन विभाग के साथ यातायात पुलिस और राज्य कर विभाग को भी शामिल किया गया है। यह संयुक्त टीम सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ कर चोरी और यातायात नियमों के उल्लंघन पर पैनी नजर रख रही है। उन्होंने बताया कि बताया कि ऑपरेशन कवच परिवहन विभाग (विशेष रूप से उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग और यातायात पुलिस) द्वारा समय-समय पर चलाया जाने वाला एक विशेष प्रवर्तन व चेकिंग अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाना, अवैध परिवहन को रोकना और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराना है।

उन्होंने बताया कि इस दो दिवसीय अभियान में यात्रियों की सुरक्षा और अवैध तरीके से माल को ले जाने तथा नियमो के उलंधन पर कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कवच सड़कों को यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए एक सुरक्षात्मक अभियान के रूप में कार्य करता है। हांलकि बारिश की वजह से अभियान की गति कुछ कम हुई है ,लेकिन निरंतर अधिकारी सड़को पर डटे हुए है।

ऑपरेशन कवच अभियान का मुख्य उद्देश्य

आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि यह अभियान ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई, मालवाहक वाहनों (जैसे ट्रक, डंपर, ट्रॉलियां) में तय क्षमता से अधिक माल ले जाने वालों पर चालान व सीज की कार्रवाई करना है। इसके साथ ही अवैध व बिना परमिट वाहनों की जांच, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, बिना वैध परमिट या बिना टैक्स जमा किए सड़कों पर चलने वाले व्यावसायिक वाहनों (बस, ऑटो, टैक्सी आदि) पर शिकंजा कसना शामिल है।

हाई डिपेंडेंसी यूनिट का प्रचार्य ने किया शुभारंभ

गंभीर प्रसूताओ की होगी विशेष देखभाल

वेब वार्ता, कानपुर। जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में हाई डिपेंडेंसी यूनिट (एचडीयू) का शुभारंभ मंगलवार मुख्य अतिथि डॉ. संजय कला, प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉ रेनू गुप्ता एवं उप प्राचार्य डॉ रिचा गिरी द्वारा किया गया। डॉ रेनू गुप्ता ने बताया कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट (एचडीयू) प्रसूति सेवाओं में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जहाँ गंभीर,लेकिन आईसीयू की आवश्यकता से कम स्तर की निगरानी वाली गर्भवती एवं प्रसूता महिलाओं को 247 विशेषज्ञ देखभाल, उनकी

मॉनिटरिंग तथा समय पर उपचार उपलब्ध कराया जाता है। इससे गंभीर जटिलताओं की शीघ्र पहचान एवं उपचार संभव होगा तथा मातृ एवं नवजात मृत्यु और गंभीर रोगग्रस्तता में कमी लाई जा सकेगी।

उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कालेज प्राचार्य प्रो. डॉ संजय काला ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक प्रसवों वाले राज्यों में से एक है, जहाँ पिछले वर्षों में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है, फिर भी रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप संबंधी विकार ,सेप्सिस तथा गंभीर एनीमिया जैसी जटिलताएँ अभी भी मातृ मृत्यु एवं मातृ मृत्यु के निकट की स्थिति के प्रमुख कारण हैं। ऐसे मामलों में समय पर गहन निगरानी और उपचार उपलब्ध कराने में एचडीयू की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी क्रम में उप प्राचार्या डॉ ऋचा गिरी ने यह भी बताया कि प्रत्येक मातृ मृत्यु के पीछे कई महिलाएँ ऐसी होती हैं जो गंभीर जटिलताओं से बाल-बाल बच जाती हैं और इन मामलों में एचडीयू जीवनरक्षक सिद्ध हो सकता है। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ नीना गुप्ता, सीएमएस डॉ अनीता गौतम, डॉ शैली अग्रवाल, डॉ बंदना शर्मा, डॉ पाविका लाल व रेजिडेंट चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ एवं बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र उपस्थित रहे।

यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को मिलेगा 20 करोड़ का ब्याजमुक्त ऋण

लखनऊ, 21 जुलाई (वेब वार्ता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के संचालन को गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय में प्रावधानित 20 करोड़ रुपये की धनराशि निगम को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से नवगठित निगम के संचालन को मजबूती मिलेगी व प्रदेश में आउटसोर्स सेवाओं के प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी नामांकन अभियान- 2026 किया प्रारम्भ

वेब वार्ता, कानपुर

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) द्वारा कर्मचारी नामांकन अभियान - 2026 प्रारम्भ किया गया है। यह एक विशेष एकमुश्त अभियान है, जिसका उद्देश्य ऐसे वर्तमान में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है, जिन्हें पूर्व में किसी कारणवश ईपीएफओ के अंतर्गत आच्छादित नहीं किया जा सका। यह अभियान दिनांक 29 जून 2026 को अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 तथा कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 2026 पैरा -60, तथा कर्मचारी पेंशन योजना, 2026 के प्रावधानों के अनुपालन में प्रारम्भ किया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 के पैरा-60 के अंतर्गत अधिसूचित कर्म्चारी नामांकन अभियान- 2026 के विशेष प्रावधानों के अनुसार ऐसे कर्मचारी, जो 01 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के मध्य किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत रहे

अथवा वर्तमान में कार्यरत हैं तथा किसी कारणवश कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य के रूप में आच्छादित नहीं किए गए हैं, उन्हें निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घोषित कर ईपीएफओ के अंतर्गत आच्छादित किया जा सकता है। इस अभियान के अंतर्गत नियोक्ताओं को उक्त अवधि के ऐसे पात्र कर्मचारियों का स्वैच्छिक नामांकन कराने का विशेष अवसर प्रदान किया गया है। इससे पात्र कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन तथा कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। अभियान के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन नियोक्ताओं को विशेष राहत का प्रावधान भी उपलब्ध कराया गया है। जिन मामलों में संबंधित अवधि के दौरान कर्मचारियों के वेतन से कर्मचारी अंशदान की कटौती नहीं की गई थी, उन मामलों में निर्धारित शर्तों के अनुसार कर्मचारी अंशदान की वसूली से छूट प्रदान की गई है।

पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने का सुनहरा अवसर

कैसे ले योजना का लाभ

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठान द्वारा सभी वर्तमान पात्र कर्मचारियों को इस अभियान के अंतर्गत घोषित किया गया है तथा कर्मचारियों से काटी गई किसी भी अंशदान राशि का कोई बकाया शेष नहीं है। साथ ही, इस अभियान के अंतर्गत घोषणा प्रस्तुत करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध घोषणा की तिथि तक सेवा छोड़ चुके कर्मचारियों के संबंध में नियमानुसार पृथक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जाएगी। ईपीएफओ का यह अभियान 01 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा तथा नियोक्ता ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं ह्ल ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर ने सभी पात्र नियोक्ताओं एवं प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे इस विशेष अवसर का लाभ उठाते हुए अपने सभी वर्तमान पात्र कर्मचारियों का नामांकन सुनिश्चित करें तथा अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना शीघ्र घोषणा-पत्र प्रस्तुत करें।

महत्वपूर्ण ख़बर

वैश्विक तबाही के रूप में प्रचारित किया जा रहा 13 नवंबर 2026 को

- नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर आगामी 13 नवंबर, 2026 की तारीख को वैश्विक तबाही के दिन के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। एक बार फिर दुनिया के अंत को लेकर भविष्यवाणियां तेजी से फैल रही हैं। इनमें दावा किया जा रहा है कि लगभग 65 साल पहले वैज्ञानिक शोधपत्र ने इस तिथि पर दुनिया के खत्म होने की आशंका जताई थी। वैज्ञानिक इस दावे का दृढ़ता से खंडन करते है और इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया बताते है। इस तरह की अफवाहें अक्सर समाज में अनावश्यक भय और भ्रम पैदा करती हैं। इस शोधपत्र में बढ़ती आबादी और सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव को लेकर भविष्य की गंभीर चुनौतियों पर गणितीय मॉडल के आधार पर चर्चा की गई थी। उस समय दुनिया भर में जनसंख्या विस्फोट को लेकर चिंताएं बढ़ रही थीं।

चार दशकों से भटक रहा विशाल हिमखंड हो चुका है अदृश्य

- वॉशिंगटन। पिछले चार दशकों से दक्षिणी महासागर में भटक रहा एक विशाल हिमखंड अब पूरी तरह से अदृश्य हो चुका है। इस विशाल हिमखंड को ए23ए के नाम से जाना जाता था। यह हिमखंड, जो आकार में गोवा राज्य से भी बड़ा और ग्रेटर लंदन के क्षेत्रफल का दोगुना था। इसकी 40 साल की लंबी और अनोखी यात्रा अब समाप्त हो गई है, और इसके अवशेष इतने छोटे हो चुके हैं कि उपग्रहों से भी इन्हें ट्रैक करना असंभव है, जिससे इसे औपचारिक रूप से गायब घोषित कर दिया गया है।

स्काईरूट की सफलता अपस्ट्रीम सेगमेंट के भविष्य के विकास के लिए अहम

यह उपलब्धि भारत में अंतरिक्ष सेवाओं के लिए साबित हो सकती है अहम मोड़

नई दिल्ली। स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा हासिल की गई ऐतिहासिक उपलब्धि देश में अंतरिक्ष सेवाओं के लिए अहम मोड़ साबित हो सकती है। स्काईरूट अपनी पहली ही कोशिश में भारत निर्मित रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा में भेजने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन (आईएसपीए) के मुताबिक करीब 9 अरब डॉलर की भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में डाउनस्ट्रीम सेगमेंट का योगदान करीब 80 फीसदी यानी 7.8 अरब डॉलर है।

रिपोर्ट के मुताबिक एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एके भट्ट ने कहा कि स्काईरूट की सफलता अपस्ट्रीम सेगमेंट के भविष्य के विकास के लिए अहम है, क्योंकि रॉकेट प्रौद्योगिकी संपूर्ण अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की कुंजी है। इस सफलता को भारत का स्पेसएक्स जैसा अहम क्षण कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रक्षेपण वाहन ही वह कुंजी है जो इन सभी अवसरों के द्वार खोलती है। अपस्ट्रीम क्षेत्र में भारत की प्रमुख निजी स्टार्टअप में स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मॉस और पिक्सल शामिल हैं,

जो रॉकेट विकास, उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

बता दें शनिवार को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रक्षेपणपथ से आगमन मिशन ने उड़ान भरी और विक्रम-1 ने करीब 450 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा में 60 डिग्री के झुकाव पर सामान्य गति से उड़ान भरते हुए अपने पेलोड को स्थापित कर दिया। ऐसा करके स्काईरूट उन चुनिंदा कंपनियों के समूह में शामिल हो गई जो कक्षा तक पहुंचने में सक्षम हैं। भट्ट ने कहा कि पूरी तरह से कार्बन-युक्त रॉकेट की इंजीनियरिंग की अद्भुत उपलब्धि के अलावा, यह प्रक्षेपण सार्वजनिक-निजी सह-अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

निजी अंतरिक्ष क्षेत्र अब उच्च जोखिम वाला निवेश नहीं है। यह एक अत्यंत विश्वसनीय, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी परिसंपत्ति वर्ग है जो वैश्विक लघु उपग्रह प्रक्षेपण की बाधा को दूर करने में सक्षम है। विक्रम-1 एक सात मंजिला, बहु-चरणीय कक्षीय प्रक्षेपण यान है जो पूर्णतः कार्बन मिश्रित संरचना पर निर्मित है और इसमें स्वदेशी रूप से विकसित प्रणोदन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 3डी-प्रिंटेड इंजन और उच्च-शक्ति वाले ठोस-ईंधन मोटर शामिल हैं। इसे 350 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों को निम्न पृथ्वी कक्षा में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस उड़ान में, विक्रम-1 ने ग्रह स्पेस, कॉस्मोसर्व और डीक्यूबेड के प्रौद्योगिकी-प्रदर्शन पेलोड के साथ-साथ स्काईरूट के अपने स्कोप उपग्रह, कॉस्मोस डायमंड्स की कलाकृति कॉस्मिक ब्लूम और एक सूक्ष्म कलाकृति को भी ले जाया गया।

सुहोरा टेक्नोलजीज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सह-संस्थापक, कृषानु आचार्य ने कहा कि कम लागत वाली और अधिक प्रतिक्रियाशील प्रक्षेपण सेवाओं से अधिक भारतीय उपग्रह ऑपरेटरों को उपग्रहों के समूह स्थापित करने और उन्हें पुनःपूर्ति करने में मदद मिलेगी, जिससे पृथ्वी अवलोकन डेटा की उपलब्धता, पुनरीक्षण आवृत्ति और समयबद्धता में उल्लेखनीय सुधार होगा। साथ ही, इससे उभरते हुए और अनुप्रयोग-केंद्रित अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए विशिष्ट उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप समर्पित उपग्रह संपत्तियों का स्वामित्व और संचालन करना भी आसान हो जाएगा।

कनाडा से आयातित सामानों पर 50 फीसदी टैरिफ का ऐलान

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक व्यापार युद्ध की चिंगारी भड़का दी है। ट्रंप ने सोमवार को पड़ोसी देश कनाडा से अमेरिका आने वाले अधिकांश सामानों पर 50 फीसदी का भारी टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी प्रशासन ने आरोप लगाया है कि कनाडा अमेरिकी ऑटोमोबाइल, शराब और डेयरी उत्पादों के साथ लगातार भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहा है। ट्रंप के इस फैसले से दोनों व्यापारिक साझेदार देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक तनाव काफी गहराने की आशंका जताई जा रही है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ में बढ़ोतरी से जुड़े तीन अलग-अलग प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है। इस फैसले को ट्रेड एक्ट ऑफ 1930 की धारा 338 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चीन के अलावा कनाडा ही उन चुनिंदा देशों में शामिल था, जिसने ट्रंप द्वारा पहले लगाए गए टैरिफ का करारा जवाब देते हुए जवाबी शुल्क लगाया था। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि इस तरह के कड़े रवैये के लिए कनाडा की जवाबदेही तय की जानी जरूरी थी।

हालांकि, इस नए आदेश में अमेरिका ने अपनी जरूरतों का ध्यान रखते हुए कुछ अहम क्षेत्रों को राहत भी दी है। ऊर्जा उत्पाद, पोटाश, मछली और दुर्लभ खनिजों (रेयर अर्थ मिनरल्स) को इस 50 फीसदी टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन यह भारी शुल्क उन कई उत्पादों पर भी लागू होगा, जिन्हें पहले यूनाइटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कनाडा एग्रीमेंट के तहत सीमा शुल्क से छूट मिली हुई थी। वर्ष 2020 में लागू हुआ यह ऐतिहासिक व्यापार समझौता हाल ही में खत्म हुआ था और इसे दोबारा शुरू करने पर बातचीत जारी है। अमेरिका और कनाडा की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे पर काफी निर्भर हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस अचानक उठाए गए कदम से अमेरिकी बाजार में दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे महंगाई पर दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा, डेमोक्रेटिक सांसदों ने भी चेतावनी दी है कि एकतरफा टैरिफ लगाने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है। दूसरी तरफ, ट्रंप प्रशासन पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है और अधिकारियों को कनाडा पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

कच्चे तेल में तेजी से अमेरिका-पाकिस्तान में बढ़े पेट्रोल के दाम

वॉशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 90 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। वैश्विक बाजार में आए इस उछाल का असर दुनिया भर के देशों में दिखना शुरू हो गया है, जहां ईंधन के दाम बढ़ाकर इसका बोझ आम जनता पर डाला जा रहा है। अमेरिका में पेट्रोल की राष्ट्रीय औसत खुदरा कीमत एक बार फिर बढ़कर 4 डॉलर प्रति गैलन पर पहुंच गई है, जो एक साल पहले 3.14 डॉलर प्रति गैलन थी।

पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी आते ही तुरंत पेट्रोल के दाम 13.18 रुपये बढ़ाकर 310.71 रुपये प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल के दाम 13.80 रुपये बढ़ाकर 323.30 रुपये प्रति लीटर कर दिए हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका (150.72 रुपये), साइप्रस, यूक्रेन, स्पेन और इटली (206.95 रुपये) जैसे कई देशों में भी पेट्रोल की कीमतें 150 से 200 रुपये प्रति लीटर से ऊपर जा चुकी हैं। इन सब के बीच भारत में फिलहाल पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उपभोक्ताओं को राहत बनी हुई है। हालांकि, यदि पश्चिम एशिया में संकट लंबा खींचता है तो भारत के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, जिससे व्यापार घाटा और चालू खाते का घाटा बढ़ने की आशंका है।

इसके अलावा होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा के चलते अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों को लंबे वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है।

परिवहन दूरी बढ़ने और युद्ध जोखिम बीमा प्रीमियम में उछाल से आयात-निर्यात का खर्च काफी बढ़ गया है। निर्यात मामलों के जानकारों का कहना है कि कई वैश्विक मार्गों पर शिपमेंट लागत दोगुनी से अधिक हो चुकी है। यदि स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो केवल ईंधन ही नहीं, बल्कि उर्वरक, रसायन, पेट्रोकेमिकल उत्पाद, खाद्य पदार्थ और रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत भी बढ़ जाएगी, जिससे देश में व्यापक महंगाई का दबाव बढ़ सकता है।

पूर्वी अफगानिस्तान में कुदरत का कहर: भीषण बाढ़ से 20 लोगों की मौत

100 से अधिक लापता लोगों की तलाश जारी

काबुल। भारतीय उपमहाद्वीप में इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है।

भारत और चीन के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त-व्यस्त होने के बीच अब पूर्वी अफगानिस्तान में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अफगान आपदा प्रबंधन अधिकारियों के अनुसार, इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80 से अधिक लोग घायल हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में

राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं।

अफगानिस्तान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, प्राकृतिक आपदा का सबसे भयंकर प्रभाव पूर्वी प्रांत नूरिस्तान में पड़ा है। यहां पारून और आसपास के कई इलाकों में अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) ने भारी तबाही मचाई है। उफनती नदियों और पहाड़ों से आए पानी के तेज बहाव में सैकड़ों मकान ढह गए और बड़े पैमाने पर फसलें जलमग्न हो गईं। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और वीडियो में मिट्टी के बने घरों को ताश के पत्तों की तरह ढहते और बेबस लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भागते देखा जा सकता है। मौसम की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने देश के 34 में से 10 प्रांतों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मूसलाधार बारिश, गरज-चमक के साथ तेज हवाओं, धूल भरी आंधी और अचानक बाढ़ आने की चेतावनी दी है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे नदियों के तटों और संभावित जोखिम वाले संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहें। अफगानिस्तान में दशकों पुराने संघर्ष, खस्ताहाल बुनियादी ढांचे, कमजोर अर्थव्यवस्था, अंधाधुंध जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के असर ने इस तबाही को और अधिक बढ़ा दिया है। खासकर दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में बने कच्चे मिट्टी के मकान बाढ़ के तेज थपेड़ों को सहने में पूरी तरह असमर्थ साबित होते हैं। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष की शुरूआत में भी देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 110 से अधिक लोगों की जान जा चुकी थी।

अमेरिका भारत को अब कारोबारी प्रतिद्वंद्वी मानता, पाकिस्तान को बना रहा काउंटरवेट

नई दिल्ली। रणनीतिक विश्लेषक और प्रोफेसर डॉ. ब्रह्म चेलानी ने भारत-अमेरिका संबंधों की बदलती गति पर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने दावा किया है कि वॉशिंगटन भारत के प्रति अपनी नीति में एक बुनियादी बदलाव कर रहा है, इसके तहत भारत को अब केवल रणनीतिक साझेदार के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित आर्थिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देख रहा है। डॉ. चेलानी के अनुसार, यह बदलाव चुपचाप हो रहा है और इसका असर दोनों देशों के भविष्य के संबंधों पर पड़ सकता है। अपने विश्लेषण में, डॉ. चेलानी ने बताया कि अमेरिकी नीति में दबाव आधारित कूटनीति के साथ-साथ पाकिस्तान की ओर फिर से बढ़ता झुकाव यहां दिखाता है। उनका आरोप है कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता और पाकिस्तान के रक्षा ढांचे को मजबूत करने जैसे उपायों के माध्यम से भारत के क्षेत्रीय प्रभाव के मुकाबले एक काउंटरवेट (प्रतिसंतुलन) के रूप में स्थापित करने का काम कर रहा है।

चंपत भूमिका पर फैसला होगा जल्द, गवाह या सह-आरोपी बनने पर सस्पेंस

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला

अयोध्या। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के खुलासे के बाद ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय की भूमिका अब जांच के निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पूर्व महासचिव चंपत राय के बयान और गवाही को इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष के लिए बेहद मजबूत साक्ष्य माना जा रहा है। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जल्द ही यह तय हो जाएगा कि चंपत राय मुकदमे में मुख्य गवाह बनेंगे या फिर सह-आरोपी। हालांकि, अब तक की जांच में उनका पूरा सहयोग रहा है और उनके बयानों के आधार पर ही आरोपियों से पूछताछ की गई है, जिससे उनके मुख्य साक्षी बनने की संभावना अधिक दिखाई दे रही है।

एसआईटी और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, दानपात्रों के चढ़ावे की गणना के दौरान बाथरूम में कुछ रुपये मिलने के बाद इस चोरी का खुलासा हुआ था। इसके बाद सक्रिय हुए चंपत राय ने संदिग्धों की तलाश की और 5 जून को पुलिस के साथ निकलकर करीब 80 लाख रुपये बरामद करवाए थे। इसके बाद ही एसआईटी का गठन हुआ और ट्रस्टी कृष्णमोहन की शिकायत पर 8 नामजद समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यद्यपि शुरूआती स्तर पर मामले को दबाने के प्रयास और चंपत राय द्वारा दी गई सफाई के कारण उनकी भूमिका पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन बाद में विवाद बढ़ने पर उन्होंने ही राज्य सरकार से एसआईटी जांच की सिफारिश की थी। कानूनी दृष्टिकोण से चंपत राय की गवाही इस पूरे मुकदमे की नींव बनेगी। उन्होंने पूछताछ के दौरान एसआईटी और पुलिस को हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है और सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। जांच अधिकारियों का मानना है कि यदि वह अदालत में आधिकारिक तौर पर गवाही देते हैं, तो आरोपियों पर दोष सिद्ध करना आसान हो जाएगा और मुकदमा बेहद मजबूत होगा।

त्रिपुरा DGP की संदिग्ध मौत पर सियासत तेज, विपक्ष ने मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग

अगरतला। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग ढंकर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई है। विपक्षी माकपा (सीपीआई-एम) ने मामले की मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में न्यायिक जांच कराने की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र न्यायिक जांच आवश्यक है।

विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने कहा कि अनुराग ढंकर जैसे मजबूत और अनुभवी अधिकारी के आत्महत्या करने की बात सहज स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले आठ वर्षों से भाजपा सरकार के दौरान आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर लगातार राजनीतिक दबाव बनाया जाता रहा है, जिससे प्रशासनिक तंत्र में असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए न्यायपालिका की निगरानी में जांच कराई जानी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि डीजीपी अनुराग ढंकर का शव मंगलवार को पुलिस मुख्यालय स्थित उनके आधिकारिक कक्ष के वॉशरूम में फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह सचिव पुलिस मुख्यालय पहुंचे। इसके बाद उन्हें तत्काल एजीएमसी एवं जीबीपी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि डीजीपी अनुराग ढंकर का निधन अत्यंत दुखद और स्तब्ध कर देने वाला है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हालांकि, मृतक के परिजनों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं विपक्ष ने पूरे मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है।

अब बिहार के भागलपुर में निकले पिता-पुत्री कोरोना संक्रमित

दोनों मरीज जेएलएनएमसीएच में भर्ती, संपर्क में आए लोगों की जांच के निर्देश -आंध्र और महाराष्ट्र के बाद बढ़ी सतर्कता

पटना। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के नए मामलों के बाद अब बिहार में भी कोविड-19 ने दस्तक दी है।

भागलपुर जिले में 65 वर्षीय एक बुजुर्ग और उनकी 35 वर्षीय बेटी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोनों का इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जेएलएनएमसीएच) में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों मरीजों को चिकित्सकीय निगरानी में रखते हुए संपर्क में आए लोगों की जांच शुरू कर दी है।

अस्पताल अधीक्षक डॉ. एच.पी. दुबे ने सोमवार को बताया कि बुजुर्ग की तबीयत 15 जुलाई से खराब थी। प्रारंभिक उपचार एक निजी क्लिनिक में कराया गया, लेकिन कोरोना जैसे लक्षण दिखाई देने पर उन्हें जेएलएनएमसीएच रेफर किया गया। रविवार को अस्पताल में भर्ती करने के बाद उनकी आरटी-पीसीआर जांच कराई गई, जिसमें कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई।

इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित मरीज के संपर्क में आए लोगों की जांच शुरू की। जांच के दौरान उनकी 35 वर्षीय बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। अस्पताल प्रशासन के अनुसार दोनों मरीजों को अलग वार्ड में भर्ती

कर गहन चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रख रही है। अस्पताल अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जानकारी में दूसरे संक्रमित को मरीज की पत्नी बताया गया था, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि वह उनकी बेटी हैं।

भागलपुर जिला प्रशासन ने भी आधिकारिक बयान जारी कर दोनों मामलों की पुष्टि की है। प्रशासन ने जिले में कोरोना संबंधी सभी आवश्यक प्रोटोकॉल लागू करने के निर्देश दिए हैं। जिला कार्यक्रम प्रबंधक को संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उनकी जांच कराने तथा आवश्यक निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जेएलएनएमसीएच के मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. राजकमल चौधरी ने बताया कि दोनों मरीजों की स्थिति फिलहाल स्थिर है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि समय पर जांच, उपचार और आवश्यक सावधानियां संक्रमण को नियंत्रित करने में प्रभावी साबित होती हैं। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, सर्दी-खांसी या बुखार जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जांच कराएं तथा स्वच्छता और आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का पालन करें।

मुख्य समाचार

पंशुल बंसल की उपलब्धि हरियाणा सहित पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायी - मुख्यमंत्री

वेब वार्ता न्यूज एजेंसी

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर फ़रीदाबाद निवासी पंशुल बंसल ने शिष्टाचार भेंट की। पंशुल बंसल ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातक)-2026 में अखिल भारतीय स्तर पर द्वितीय रैंक प्राप्त कर हरियाणा का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने पंशुल बंसल को उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पंशुल की यह सफलता हरियाणा सहित पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। उनकी मेहनत, लगन, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण ने यह सिद्ध कर दिया है कि निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के युवा शिक्षा, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पंशुल बंसल की उपलब्धि भी इसी गौरवशाली परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने पंशुल के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देकर समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस अवसर पर पंशुल बंसल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का स्नेह, आशीर्वाद और प्रोत्साहन उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा।

मुख्यमंत्री से मिले नीट (स्नातक)-2026 में अखिल भारतीय स्तर पर द्वितीय रैंक प्राप्त करने वाले पंशुल बंसल

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मिर्जापुर माजरा व भूखड़ी पहुंचकर शोक संतप्त परिवारों को दी सांत्वना

वेब वार्ता न्यूज एजेंसी

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को उपमंडल नारायणगढ़ के गांव मिर्जापुर माजरा एवं गांव भूखड़ी पहुंचकर शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिजनों को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी सबसे पहले गांव मिर्जापुर माजरा पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय जय सिंह के निवास पर जाकर शोक व्यक्त किया। स्वर्गीय जय सिंह का 15 जुलाई को बीमारी के कारण निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने परिवारजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं तथा ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी गांव भूखड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक स्वर्गीय राजपाल भूखड़ी के निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय राजपाल भूखड़ी का 20 जुलाई को हृदयगति रुकने से निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की । उन्होंने शोकाकुल परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की।

मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में एचएडीसी की 8वीं बोर्ड बैठक संपन्न

अवसंरचना और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए

वेब वार्ता न्यूज एजेंसी

चंडीगढ़ । हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री एवं हरियाणा एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ मे हरियाणा एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 8वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में नागरिक उड्डयन अवसंरचना के विकास, एयर एम्बुलेंस सेवाओं के विस्तार, वित्तीय प्रबंधन तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने से संबंधित विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में राज्य में हेली एम्बुलेंस (मेडिकल, पर्यटन एवं सार्वजनिक परिवहन) सेवाओं के विस्तार पर विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग एवं विभिन्न अस्पतालों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए फरीदाबाद, करनाल, सोनीपत, गुरुग्राम और रोहतक स्थित मेडिकल कॉलेजों के निकट बने हेलीपैडों के उन्नयन की योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में चल रही सभी उड्डयन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ पूरा किया जाए, ताकि प्रदेश में व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो सके। बैठक में नागरिक उड्डयन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अपूर्व कुमार सिंह, वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, नागरिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक एवं सचिव श्री अंशज सिंह, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ. यश पाल तथा हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री मनीष कुमार लोहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि, विद्यार्थियों ने निबंधों के माध्यम से किया स्मरण

वेब वार्ता न्यूज एजेंसी

रोहतक। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में मंगलवार को कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रभक्ति और शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को समर्पित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई तथा मानविकी संकाय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत कारगिल विजय दिवस विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के 40 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी. एम. यादव ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारत के वीर सैनिकों के अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज का युवा देश का भविष्य है और विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, कर्तव्यनिष्ठा तथा देश के प्रति समर्पण की भावना विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे कारगिल के अमर शहीदों के त्याग और बलिदान से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं तथा उनके आदर्शों को सदैव स्मरण रखें। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. विनोद कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने विपरीत परिस्थितियों में भी अद्वितीय साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए देश की सीमाओं की रक्षा की। उनका बलिदान प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणास्रोत है और युवाओं को उनके आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण को बनाएं जन आंदोलन- मुख्यमंत्री

पर्यावरण बचाओ संदेश जन जन तक पंहुचाने के लिए वन चेतना यात्रा -2026 की चार एलईडी वैन को झंडी दिखाकर किया रवाना

वेब वार्ता न्यूज एजेंसी

पंचकूला । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी संस्कृति में प्रकृति को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। पर्यावरण की रक्षा हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारे कर्तव्यों में रचा बसा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम को राष्ट्रव्यापी अभियान से जोड़ना है। मुख्यमंत्री मंगलवार को पंचकूला के पिंजौर की एप्पल मार्केट में युवा संवाद एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यातिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे।

इससे पहले , मुख्यमंत्री ने वन, पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह के साथ एप्पल मंडी में पौधारोपण भी किया और वन चेतना यात्रा -2026 के तहत चार एलईडी वैनस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। ये एलईडी वैन प्रत्येक जिले में जाएगी लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगी और पर्यावरण बचाओ का संदेश देंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने थापली नेचर कैंप में भाग लेने वाले युवाओं को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, विधायक शक्ति रानी भी मौजूद रहे।इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत एक हजार युवाओं को शामिल करने की घोषणा की। इसके अलावा युवाओं की समस्याओं की सुनवाई के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने तथा मोरनी में टिक्करताल का मनाली की तर्ज पर पर्वतारोहण प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने तथा इसका आधारभूत संरचना सुदृढीकरण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने पिंजौर सेब मंडी में बिजली आपूर्ति के लिए अलग से सब स्टेशन तथा हिमाचल प्रदेश की ओर से सेब लाने वाले वाहनों की पार्किंग व अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधा लगाना आसान है, लेकिन उसे वृक्ष बनाना बड़ी जिम्मेदारी है। जिस दिन हर युवा अपने जन्मदिन, अपने माता-पिता के जन्मदिन या किसी विशेष अवसर पर एक पौधा लगाकर, उसकी देखभाल करने का संकल्प ले लेगा, उस दिन हरियाणा प्रदेश हरा भरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कथन अनुसार जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली मां को देते हैं, उतना ही सम्मान हमें हमारा पालन पोषण करने वाली धरती मां को भी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए इस अभियान को और गति देनी होगी। हम सब जीवनदायिनी धरती मां के लिए एक पेड़ जरूर लगाएंगें तथा दूसरों को भी प्रेरित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे पेड़ जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है ऐसे पेड़ों की देखभाल के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता का भाव हम सभी में होना चाहिए। इसी उदेश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है। इसके तहत 3,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन दी जा रही है।

वन पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि पर्यावरण में सुधार लाने के लिए दो पेड़ लगाकर उनका पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री के विकसित भारत विजन 2047 में अहम भूमिका निभाने के लिए हमें स्वच्छ क्षेत्र बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना चाहिए है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हर वर्ष दो पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए स्किल डिवलेपमेंट विकसित करने के लिए उद्योगों में प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया है। उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई उद्योग नीति संचालित की जा रही है। इसके सार्थक परिणाम आ रहे है। उद्योग नीति में 5 से 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। जबकि अब तक एक लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। उन्होंने कहा कि उद्योग लगेंगे तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुलभ होंगे।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपना वोट अवश्य बनवाए- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री ने पिंजौर के मानकपुर गांव स्थित देवीलाल कॉलोनी में आयोजित टिफिन बैठक में लिया भाग

वेब वार्ता न्यूज एजेंसी

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना वोट अवश्य बनवाना चाहिए। बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के सहयोग के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करता है, जो मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने तथा अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों में लोगों का सहयोग करते हैं।

इसी कड़ी में आज प्रदेशभर में पार्टी द्वारा शक्ति केंद्रों पर 30 टिफिन बैठकों का आयोजन किया गया। पिंजौर के मानकपुर गांव स्थित देवीलाल कॉलोनी में आयोजित एक टिफिन बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वयं भाग लिया और पार्टी संगठन की मजबूती के लिए बीएलए तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर कालका की विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, जिलाध्यक्ष श्री अजय मित्तल, मंडलाध्यक्ष श्री हरीश मोंगा, भाजपा बीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री सुनील धीमान, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती पवन कुमारी, वार्ड पार्षद श्री गुलशन ठाकुर तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रत्येक परिवार को आवास उपलब्ध करवाने के संकल्प को प्रदेश में प्रभावी रूप से साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। वे योजनाओं के लाभार्थियों के घर जाकर भी उनसे योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभ की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

इसी क्रम में आज उन्होंने हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना-2 के अनुसूचित जाति के दो लाभार्थियों, श्रीमती सरोज और श्रीमती जयंती, के घर जाकर उनसे मुलाकात की तथा उनके साथ भोजन भी किया। इन दोनों लाभार्थियों को योजना के तहत पिंजौर के सेक्टर-28 स्थित मानकपुर गांव में 30-30 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए गए हैं।

ट्रीटेड पानी का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए-मुख्यमंत्री

हरियाणा के थर्मल पावर प्लांटों तक पहुंचेगा ट्रीटेड पानी, औद्योगिक क्षेत्रों में भी होगा इस्तेमाल

वेब वार्ता न्यूज एजेंसी

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, ट्रीटेड वॉटर सप्लाई के संबंध में चंडीगढ़ में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए। साथ में हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा। (21.07.2026)

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जल संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि ट्रीटेड पानी का वैज्ञानिक और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए तो न केवल भूजल और पेयजल स्रोतों पर दबाव कम होगा, बल्कि उद्योगों, ऊर्जा क्षेत्र, हरित क्षेत्रों और कृषि के लिए भी पानी की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री सोमवार देर सांय रीयूज़ ऑफ ट्रीटेड वेस्टवॉटर (टीडब्ल्यूडब्ल्यू) पॉलिसी, हरियाणा से संबंधित विशेष बैठक ले रहे थे। बैठक में प्रदेश के जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीटीपी) से तय मानकों के अनुरूप ट्रीटेड पानी निकले और उसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रीटेड पानी किसी भी स्थिति में व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसके लिए ऐसा मजबूत और सुव्यवस्थित नेटवर्क तैयार किया जाए, जिससे यह पानी थर्मल पावर प्लांटों, ग्रीन बेल्ट, कृषि और अन्य जरुरत वाले क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच सके।

बैठक के दौरान जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने ट्रीटेड वेस्ट वाटर के दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध योजना बनाई है। पहले चरण में 21 जिलों के 35 एसटीपी को शामिल करते हुए 500 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की गई, जिसे नाबार्ड के तहत मंजूरी मिली। इनमें 27 एसटीपी को माइक्रो इरिगेशन के जरिए ट्रीटेड वेस्ट वाटर के दोबारा इस्तेमाल के लिए अंतिम रूप दिया गया है। 19 एसटीपी का काम पूरा हो चुका है, जबकि 8 पर काम चल रहा है। इस परियोजना से करीब 40 हजार एकड़ खेती की जमीन को सिंचाई जल मिलेगा।अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि दूसरे चरण में 57 एसटीपी को शामिल किया गया है। इनमें 13 एसटीपी की क्षमता 157.50 एमएलडी और 44 एसटीपी की क्षमता 370.75 एमएलडी है। फिलहाल राज्य में 207 एसटीपी/सीईटीपी हैं और बाकी प्लांट्स को भी चरणबद्ध तरीके से इस योजना से जोड़ा जाएगा।

विभाग ने पहले चरण की परियोजनाएं समय पर पूरी करने, दूसरे चरण के व्यवहारिक एसटीपी विकसित करने और बाकी एसटीपी को भी इस योजना से जोड़ने की तैयारी की है। लक्ष्य है कि विजन@ 2047 के तहत मार्च 2031 तक राज्य में 100 फीसदी ट्रीटेड वेस्ट वाटर का दोबारा इस्तेमाल किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में जहां-जहां एसटीपी और सीटीपी स्थापित हैं, उनकी विस्तृत मैपिंग की जाए। प्रत्येक प्लांट की क्षमता, वहां से निकलने वाले ट्रीटेड पानी की मात्रा, उसके संभावित उपयोग और आसपास के क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था का पूरा खाका तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि सही योजना और बेहतर समन्वय के साथ ट्रीटेड पानी का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा सकता है, जिससे भूजल और पेयजल स्रोतों पर दबाव भी कम होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि ट्रीटेड पानी के उपयोग में सबसे पहले थर्मल पावर प्लांटों को प्राथमिकता दी जाए। इसके बाद ग्रीन बेल्ट, पार्कों, पौधारोपण और कृषि कार्यों में इसका अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी अलग से योजना तैयार की जाए, ताकि उद्योगों में भी ताजे पानी की जगह ट्रीटेड पानी का उपयोग बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस पूरी व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कार्य केवल एक विभाग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित सभी संबंधित विभाग संयुक्त रूप से कार्ययोजना तैयार करें। इसके लिए विभागों के वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से बैठक करें और पूरे कार्य की क्लोज मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सोसायटी कॉलोनियों में स्थापित एसटीपी की भी विशेष जांच की जाएगी।

नशे से दूरी ही सुनहरे भविष्य की गारंटी, युवा अपने सपनों को नशे की भेंट न चढ़ाएः डीसी डॉ. हरीश वशिष्ठ

जागरूकता, संकल्प और प्रेरणा से ही जीती जाएगी नशे के खिलाफ जंगः- संदीप जिंदल

वेब वार्ता न्यूज एजेंसी

पानीपत । हरियाणा उदय पहल के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा नशा मुक्त हरियाणा-ड्रग फ्री पानीपत अभियान के तहत मंगलवार को आर्य कॉलेज ऑडिटोरियम में भव्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रीन मिशन एवं प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों, सामाजिक संस्थाओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लेकर नशामुक्त समाज बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण भी किया गया तथा उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ का विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया।

उपायुक्त डॉ. हरीश वशिष्ठ ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लेकर कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक जागरूकता अभियान नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि नशे से दूर रहकर ही युवा अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। नशे की गिरफ्त में आने वाला व्यक्ति केवल अपना स्वास्थ्य ही नहीं खोता बल्कि धीरे-धीरे चोरी, अपराध और सामाजिक बुराइयों की ओर भी बढ़ने लगता है। उन्होंने कहा कि किसी युवा को नशे की लत में तड़पते देखना अत्यंत पीड़ादायक होता है, इसलिए समय रहते जागरूक होना जरूरी है।

उपायुक्त ने कहा कि युवाओं को अपने चरित्र को मजबूत बनाना चाहिए, जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों का मानसिक स्तर सकारात्मक बना रहे, इसी उद्देश्य से मोटिवेशनल सत्र आयोजित किए गए हैं ताकि वे जीवन में सही दिशा चुन सकें। उन्होंने विद्यार्थियों और अभिभावकों से संवाद करते हुए उनके सुझाव भी लिए और कहा कि समाज, परिवार, विद्यालय तथा प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से ही नशे पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से प्रेरणादायक व्यक्तित्वों को अपना आदर्श बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि अच्छे आदर्श जीवन को बुराइयों से दूर रखने की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन के लिए एडवोकेट संदीप जिंदल और उनकी पूरी टीम की प्रशंसा करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। नगराधीश टीनू पोसवाल ने कहा कि नशा आज समाज के सामने गंभीर चुनौती बन चुका है और इसके खिलाफ जागरूकता सबसे सशक्त हथियार है। उन्होंने कहा कि यदि हर परिवार, विद्यालय और समाज का प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक नशे के खिलाफ अभियान से जुड़े तो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य दिया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन अपनाने की अपील की। हरियाणा उदय कार्यक्रम से जुड़े एडवोकेट संदीप जिंदल ने कहा कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ड्रग फ्री अभियान से प्रेरित होकर आयोजित किया गया है। विगत दिनों में पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पानीपत टीम की खुले मन से प्रशंसा की थी। इस अभियान में हरियाणा उदय कार्यक्रम के विशेष अधिकारी आईपीएस पंकज नैन ने भी पानीपत की सभी संस्थाओं को आगे आने के लिए आह्वान किया है। वे इस अभियान को जिला प्रशासन के साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगें और इस कार्य में सभी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपायुक्त डॉ. हरीश वशिष्ठ ने जिस तरह से इस अभियान में हर युवा को जोडने का संकल्प लिया है। उससे इस अभियान को नई दिशा और बल मिलेगा।

सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र कंसल ने कहा कि नशा परिवारों को बर्बाद कर देता है और समाज की नींव को कमजोर करता है। उन्होंने युवाओं से जीवनभर नशे से दूर रहने का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच ही सफलता की असली कुंजी है। ड्रग कंट्रोलर विजय राजे ने जिले में नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई और प्रशासन द्वारा नशा तस्करों पर लगातार कसे जा रहे शिकंजे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कानून के साथ-साथ जनजागरूकता भी इस लड़ाई का महत्वपूर्ण आधार है।

नारी तू - नारायणी सेवा समिति की अध्यक्ष सविता आर्य ने कहा कि पानीपत की इसी ऐतिहासिक धरती से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेटी बचाओ-बेटी पढाओ अभियान की शुरूआत की थी। इसी धरती से अब पर्यावरण बचाने की मुहिम को भी आगे ले जाना होगा। उन्होंने कहा कि नारी तू - नारायणी सेवा समिति इस कार्य में जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और पानीपत को हरा-भरा बनाने में कोई कोर कसर नही छोड़ी जाएगी। कार्यक्रम में लखनऊ के अमित मिश्रा ने अपने जीवन का अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने 27 वर्षों तक लगातार नशा किया और इस दौरान लगभग ढाई करोड़ रुपये बर्बाद कर दिए। उपचार और दृढ़ संकल्प के बाद आज वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे नशे की शुरुआत ही न करें, क्योंकि इससे बाहर निकलने की कीमत बहुत बड़ी होती है। सामाजिक संस्था के सदस्य तुषार द्वारा बनाई गई लघु फिल्म की भी सबने सराहना की। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से नशा मुक्त जिला बनाने को लेकर चलाए गए अभियान को भी डॉ. ललित वर्मा ने एक डाक्यूमेंट्री के माध्यम से सभी को दिखाया। उन्होंने कहा कि किस प्रकार नशा पूरे परिवार को बर्बादी की ओर धकेल देता है और समय रहते सही उपचार एवं जागरूकता से इससे बचा जा सकता है। फिल्म और प्रस्तुति ने विद्यार्थियों और उपस्थित लोगों को गहराई से प्रभावित किया।

इस अवसर पर एसडीएम इसराना नवदीप नैन, जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा, सीएमओ डॉ. विजय मलिक, नगराधीश टीनू पोसवाल, मनोचिकित्सक डॉ. अमित मलिक, जगदीश धमीजा, गौरव गोयल, डॉ. ललित वर्मा, ड्रग कंट्रोलर विजय राज, सविता आर्य, मुकेश कुमार, तुषार चावला, नरेश वर्मा, सीए भूपेंद्र दीक्षित, पार्षद नवल जिंदल, सुरेश काबरा, वेद चावला, भूपेंद्र सग्गू, धनंजय सिंगला, काकू अग्रवाल, विमल गोयल, ज्योति भाटिया, परवीन ताया,अमित गुप्ता आदि सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, शिक्षक, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन ड्रग फ्री पानीपत-नशा मुक्त हरियाणा के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ।

बांग्लादेश के कप्तान लिटन पर कार्रवाई कर सकती है बीसीबी

ढ़ाका। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के टी20 कप्तान लिटन दास की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लिटन अपनी चीन यात्रा के कारण निशाने पर हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने उन्हें अनुबंधित खिलाड़ियों के लिए तय नियमों के उल्लंघन के आरोप में अनुशासन समिति के सामने पेश होने को भी कहा हहै। इस क्रिकेटर पर आरोप है कि कि चोट से उबरने के दौरान ही वह बोर्ड को बताये बिन ही चीन यात्रा पर गये थे।

लिटन को 20 जुलाई को अपनी पिंडली (काफ) की चोट की विशेष जांच के लिए सिंगापुर जाना था। इसी चोट के चलते वह हालिया जिम्बाब्वे टी20 सीरीज और आगामी लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) 2026 से भी बाहर हो गए थे। हालांकि, इन महत्वपूर्ण चिकित्सा निदेर्शों और टूनार्मेंट से अनुपस्थिति के बाद वह बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के चीन गये थे। केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों के लिए बोर्ड की अनुमति के बिना विदेश यात्रा करना स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन माना जाता है और बीसीबी इसे किसी भी कीमत पर सहन करने के पक्ष में नहीं है। बोर्ड अब उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और प्रस्तुत की गई मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का निर्णय लेगा।

एक रिपोर्ट के अनुसार, बीसीबी के एक आंतरिक सूत्र ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा, लिटन चीन गए थे, जिसे बोर्ड ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। बोर्ड ने उन्हें बुलाकर यह जानने का प्रयास किया कि वह किसकी अनुमति से और किस उद्देश्य से चीन गए थे। इस घटना के लिटन ने बीसीबी को अपना जवाब दे दिया है। माना बीसीसबी की मेडिकल कमेटी लिटन दास के दावों और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सा दस्तावेजों की गहन जांच करेगी। इस जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही बोर्ड यह तय करेगा कि उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी या नहीं।

क्रिकेट को वैश्विक खेल बनाना है तो छोटी टीमों को बड़ी टीमों से मुकाबलों का अवसर मिले: अश्विन

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि यदि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) क्रिकेट को वैश्विक खेल बनाना है तो उभरती हुई टीमों को नियमित अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने का अवसर मिले। अश्विन के अनुसार हाल में आईसीसी ने जिस प्रकार से टीमों की संख्या बढ़ाई है उसका तब तक फायदा नहीं मिलेगा जब तक कि इन छोटी टीमों को बड़ी टीमों के खिलाफ पर्याप्त अवसर न मिले।

आईसीसी ने कुछ समय पहले ही एकदिवसीय विश्व कप और 2028 के टी-20 विश्व कप के प्रारूप में बड़े बदलावों की घोषणा की थी। नए प्रारूप के तहत साल 2027 के एकदिवसीय विश्व कप में 14 टीमें हिस्सा लेंगी और प्रतियोगिता को तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा। जिससे मुकाबलों की संख्या और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ेंगी। वहीं, 2028 के टी-20 विश्व कप में भी दूसरे चरण में अधिक टीमों को शामिल करने की योजना है, ताकि टूनार्मेंट और अधिक रोमांचक बन सके।

अश्विन का मानना है कि प्रतिस्पर्धा के लिहाज से यह कदम सही दिशा में है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा

कि, यदि अंतिम लक्ष्य क्रिकेट का वैश्विक विस्तार करना है, तो उभरते देशों के लिए एक मजबूत व्यवस्था तैयार करनी होगी। इस अनुभवी स्पिनर ने सुझाव दिया कि नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, नेपाल, अमेरिका और आयरलैंड जैसी टीमों को हर द्विपक्षीय श्रृंखला में तीसरी टीम के रूप में शामिल किया जा सकता है। उनका तर्क है कि इससे इन देशों को केवल क्वालीफाइंग प्रतियोगिताओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि उन्हें शीर्ष स्तर के देशों के खिलाफ नियमित अनुभव मिलेगा।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, नेपाल, स्कॉटलैंड और अमेरिका जैसी टीमों ने सीमित अवसरों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। टी-20 विश्व कप जैसे बड़े मंचों पर भी इन टीमों ने कई मजबूत देशों को कड़ी चुनौती देकर अपनी क्षमता साबित की है, जो दशार्ता है कि सही मंच मिलने पर ये टीमें क्रिकेट के स्तर को और ऊंचा उठा सकती हैं।

अश्विन ने इस बात पर जोर दिया कि यदि सभी देशों को बराबर अवसर मिलेंगे, तो क्रिकेट का स्तर और लोकप्रियता दोनों बढ़ेंगे। उनका मानना है कि सामूहिक विकास ही इस खेल को ओलंपिक जैसे वैश्विक मंच पर और अधिक आकर्षक बना सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में क्रिकेट की सफलता केवल भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या अन्य बड़ी टीमों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि नए देशों को भी आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए।

टेस्ट क्रिकेट में लारा, हेडन सहित इन बल्लेबाजों ने खेलीं हैं रिकार्ड लंबी पारियां

मुम्बई। सीमिति ओवरों के मुकाबलों के बीच भी टेस्ट क्रिकेट का आकर्षण बना हुआ है। इसका कारण है कि लंबे प्रारुप में ही किसी खिलाड़ी की असली परीक्षा होती है। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में कई ऐसी पारियां खेली गई हैं, जिन्होंने आज भी प्रशंसक याद रखते हैं। वहीं इस दौरान बने रिकार्ड अब भी कायम हैं। टेस्ट इतिहास की सबसे लंबी पारी खेलने का रिकार्ड वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा के नाम है। साल 2004 में सेंट जॉन्स के एंटीगा रिक्रिएशन ग्राउंड पर लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में 400 रन बनाकर सभी को हैरान कर दिया। क्रिकेट में इससे पहले किसी भी बल्लेबाज ने इतने रन नहीं बनाये थे। लारा इस मैच में 14वें ओवर में क्रीज पर आए और फिर 582 गेंदों में 43 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 400 रन बनाकर नाबाद पेवेलियन लौटे। यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास का पहला अवसर था जब कोई खिलाड़ी 400 रन तक पहुंचा। इससे पहले साल 2003 में पर्थ के वाका मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 146 ओवरों तक बल्लेबाजी की और 380 रन बनाए, जिसमें 38 चौके और 11 छक्के शामिल थे। साल 2006 में कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर श्रीलंका के तत्कालीन कप्तान महेला जयवर्धने ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक ऐतिहासिक पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका को 169 रन पर सिमटने के बाद, श्रीलंका ने भी अपने 14 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद महेला जयवर्धने और कुमार संगकारा ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 624 रनों की विश्व रिकॉर्ड साझेदारी की। संगकारा 287 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन जयवर्धने टिके रहे और 572 गेंदों में 43 चौकों और 1 छक्के की मदद से 374 रन बनाकर आउट हुए।

युवराज ने चयन पर उठाए सवाल, यशस्वी को पर्याप्त अवसर नहीं मिलने पर जतायी चिन्ता

सीनियर खिलाड़ियों के लिए साफ रोडमैप जारी करें

चंडीगढ़। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के चयन मापदंडों पर सवाल उठाये हैं। उन्होंने युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को पर्याप्त अवसर नहीं मिलने और अनुभवी खिलाड़ियों के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की कमी को लेकर अपनी चिंताएं साझा की हैं। युवराज ने कहा कि आगामी विश्व कप से पहले टीम प्रबंधन को इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की जरुरत है।

युवराज ने कहा कि वह विशेष रूप से युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल लेकर चिन्ता जतायी है। युवराज के अनुसार यशस्वी ने हाल के अपने तीन एकदिवसीय मैचों में दो शानदार शतक लगाये हैं। इसके बाद भी उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, यशस्वी को खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे में अगर विश्व कप से पहले उन्हें खेलने का पर्याप्त समय नहीं मिलता और टीम में शामिल किया जाता है तो उन पर अचानक ही दबाव बन जाएगा। पिछले महीने चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद शतक बनाने के बावजूद जायसवाल को इंग्लैंड के खिलाफ आगामी एकदिवसीय सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया था। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की फॉर्म और टीम में उनकी जगह को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं।

इस पूर्व शानदार ऑलराउंडर ने जोर देकर कहा कि अगर जायसवाल टीम की विश्व कप योजनाओं का हिस्सा हैं, तो उन्हें बड़े टूनार्मेंट से पहले और अधिक मैच खेलने की आवश्यकता है जिससे वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुभव प्राप्त कर सकें और दबाव का सामना करना सीख सकें। युवराज ने 2019 विश्व कप का उदाहरण देते हुए चेतावनी दी, जहां चोट के कारण दो युवा खिलाड़ियों को बिना अधिक अनुभव के टीम में शामिल करना पड़ा था, और ऐसी पुरानी गलतियों को दोहराने से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? हमने पहले भी ऐसा होते देखा है।

युवराज ने अनुभवी खिलाड़ियों के प्रति प्रबंधन के दृष्टिकोण पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि प्रबंधन को अपने सीनियर खिलाड़ियों को एक साफ रोडमैप देना चाहिए, चाहे वे टीम की दीर्घकालिक योजनाओं का हिस्सा हों या न हों। युवराज का मानना है कि आदर्श रूप से, टीम में अनुभव और युवा खिलाड़ियों का एक संतुलित मिश्रण होना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली विश्व कप के लिए आपकी योजनाओं का हिस्सा हैं, तो उन्हें अभी बताएं और उनकी जगह पक्की करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उम्र और फॉर्म को लेकर बाहरी चचाएँ तो होती रहेंगी पर प्रबंधन को अपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ आंतरिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट रखनी चाहिए। युवराज ने ईमानदारी की वकालत करते हुए कहा, और अगर कोई आपकी योजनाओं में नहीं है, तो उनसे ईमानदारी से बात करें। यह एक मुश्किल फैसला होगा, बाहर से शायद यह बुरा लगे, लेकिन वे इस बात की तारीफ करेंगे कि आपने उनसे सीधे बात की। उनका मानना है कि इस तरह की स्पष्ट और सीधी बातचीत खिलाड़ियों में विश्वास पैदा करती है और उन्हें अपने भविष्य के बारे में फैसला लेने में मदद करती है, जो अंततः टीम के हित में ही होता है।

कुलदीप को अवसर नहीं मिलने का कारण शुभमन ने बताया

लंदन। भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव को इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज में एक भी मुकाबला खेलने का अवसर नहीं मिला। यहां तक कि लॉर्ड्स में खेले गए निर्णायक तीसरे एकदिवसीय में भी उन्हें अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली जबकि मैच के दौरान स्पिनरों को काफी सहायता मिली। इसी को लेकर कप्तान शुभमन गिल ने सफाई दी है शुभमन ने कहा कि शुरूआती दोनों एकदिवसीय में पिच से स्पिनरों को अधिक सहायता नहीं मिली। इसी कारण टीम प्रबंधन ने अतिरिक्त स्पिनर खिलाने की जगह पर तेज

गेंदबाजों पर भरोसा जताया था। गिल ने कहा, पहले दो मैचों में हमने देखा कि पिच स्पिनरों के लिए ज्यादा सहायक नहीं थी। जब स्पिनर गेंदबाजी करते थे तो हमें रक्षात्मक फील्ड लगानी पड़ती थी, जबकि तेज गेंदबाजों के साथ विकेट मिलने की संभावना ज्यादा दिख रही थी। इसी कारण से कुलदीप को टीम में जगह नहीं मिली।

लॉर्ड्स में हुए मैच को लेकर शुभकन ने कहा कि मुकाबला आगे बढ़ने के साथ विकेट धीमा हो गया और बाद में स्पिन गेंदबाजी ज्यादा प्रभावी साबित हो सकती थी। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए कहा, अब देखें तो लगता है कि स्पिनर बेहतर विकल्प हो सकता था। जब हम गेंदबाजी कर रहे थे तब ऐसा नहीं लग रहा था कि विकेट इतना धीमा होगा, लेकिन दूसरी पारी में पिच काफी धीमी हो गई। भारत की यह रणनीति मैदान पर सफल नहीं रही। टीम के चारों तेज गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए और महत्वपूर्ण विकेट लेने में नाकाम रहे।कुलदीप ने अपना पिछला एकदिवसय जून में अफगानिस्तान के खिलाफ लखनऊ में खेला था, जिसमें उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। कुलदीप यादव का इंग्लैंड में रिकॉर्ड काफी सम्मानजनक रहा है। उन्होंने यहां अब तक 10 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें 15 विकेट लिए हैं। भारतीय टीम अब भारत अब सितंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू एकदिवसीय सीरीज खेलेगी और देखना होगा कि उसमें कुलदीप को अवसर मिलत है या नहीं।

कारोबार

सर्राफा बाजार में जबरदस्त उछाल, सोना खरीदना हुआ महंगा; चांदी की कीमतों में 2600 रुपये की तेजी

नई दिल्ली। भारतीय सराफा बाजार में पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट देखने को मिली. लेकिन इस सप्ताह सराफा बाजार में हर दिन उछाल देखने को मिल रहा है. सोमवार के बाद मंगलवार को भी बाजार की शुरूआत उछाल के साथ हुई. शुरूआती कारोबार में ही सोना 900 रुपये से ज्यादा के उछाल के साथ कारोबार करता दिखा. जबकि चांदी का भाव 2600 रुपये चढ़ गया. बुलियंस डॉट को डॉट इन वेबसाइट से प्राप्त डेटा के मुताबिक, मंगलवार (21 जुलाई) सुबह 9.50 बजे सोना 950 रुपये और चांदी 2630 रुपये चढ़कर कारोबार करती दिखी.

आज क्या हैं सोने और चांदी के दाम?

मंगलवार को सराफा बाजार में आई तेजी के बाद 22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 131,065 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गईं. जबकि 24 कैरेट गोल्ड का भाव 142,980 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. वहीं चांदी का भाव 221,230 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है. वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (टउ) पर सोना 957 रुपये यानी 0.68 प्रतिशत के उछाल के साथ 142,345 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. जबकि चांदी का भाव यहां 2373 रुपये यानी 1.09 प्रतिशत चढ़कर 220,773 रुपये प्रति किग्रा पर पहुंच गया. वहीं विदेशी बाजार यानी यूएस कॉमेक्स पर सोना 37.70

डॉलर यानी 0.94 प्रतिशत महंगा होकर 4053.60 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. जबकि चांदी का भाव यहां 1.06 डॉलर या 1.85 प्रतिशत तेजी के साथ 58.13 डॉलर प्रति औंस हो गया है.

वहीं देश के प्रमुख शहरों की बात करें तो दिल्ली में आज सोना 1580 रुपये और चांदी 4220 रुपये महंगी होकर कारोबार कर रही है. इसके बाद यहां 22 कैरेट सोना 131,184 तो 24 कैरेट गोल्ड का भाव 143,110 रुपपे प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं चांदी का भाव 222,050 रुपये प्रति किग्रा हो गया है. मुंबई में सोना 1530 तो चांदी 4170 रुपये महंगी हुई है. अब यहां सोना (22 कैरेट) 131,358 और 24 कैरेट गोल्ड 143,300 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया है. जबकि कोलकाता में सोना 1520 रुपये बढ़कर कारोबार कर रहा है. यहां 22 कैरेट सोने का भाव 131,184 तो 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 143,110 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. वहीं चांदी 4160 रुपये चढ़कर 222,070 रुपये प्रति किग्रा पर पहुंच गई है. उधर चेन्नई में सोना-चांदी क्रमशः 1530 और 4170 रुपये महंगा होकर कारोबार कर रही है. यहां 22 कैरेट गोल्ड का भाव 131,743 तो 24 कैरेट सोने की कीमत 143,720 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. जबकि चांदी का भाव 223,010 रुपये प्रति किग्रा पर पहुंच गया है.

शेयर बाजार में सुस्ती, वैश्विक तनाव व महंगे क्रूड ने सेंसेक्स-निफ्टी पर बढ़ाया दबाव

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रुपये की कमजोरी के बीच भारतीय शेयर बाजार की फ्लैट शुरूआत हुई है। पूरी रिपोर्ट और वैश्विक बाजार के ताजा अपडेट के लिए अभी पढ़ें।

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों की शुरूआत फ्लैट रही है। आज सुबह सेंसेक्स और निफ्टी में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिला। वैश्विक संकेतों और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार बिकवाली के कारण विशेषज्ञ बाजार के सीमित दायरे में रहने की उम्मीद जता रहे हैं। कॉरपोरेट नतीजों के सीजन के बीच चुनिंदा शेयरों में तेज एक्शन देखने को मिल सकता है।

तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरूआती कारोबार में 58.89 अंक गिरकर 77,649.63 पर आ गया। पचास शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 22.45 अंक फिसलकर 24,216.05 पर पहुंच गया। सेंसेक्स के शेयरों में, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, सन फार्मा और मारुति

जैसे शेयर नुकसान में रहे। एचडीएफसी बैंक लगातार दूसरे दिन गिरा, क्योंकि ऋणदाता की तिमाही आय मार्जिन के मोर्चे पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। वहीं, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स और एचसीएल टेक जैसे शेयर लाभ में रहे।

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार, 20 जुलाई 2026 को भारतीय इक्विटी से 1,121.04 करोड़ रुपये की निकासी की। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.63 फीसदी कम होकर 88.66 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में शेयर बाजार एक मिश्रित झुकाव के साथ सीमित दायरे में ही घूमता नजर आएगा।

कच्चे तेल की कीमतों का बाजार पर क्या असर होगा?

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि निकट भविष्य में बाजार कच्चे तेल की कीमतों के रुझानों से काफी प्रभावित होगा। उन्होंने बताया कि ब्रेंट क्रूड का करीब 88 अमेरिकी डॉलर के स्तर तक नरम होना एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि, अनिश्चितता इतनी अधिक है कि कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि का जोखिम बना हुआ है। विजयकुमार के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में संभावित वृद्धि बाजारों पर अतिरिक्त दबाव डालेगी। यह स्थिति निवेशकों की धारणा को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।

एनरिच मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोनमुडी आर ने बताया कि बाहरी चुनौतियों के संयोजन ने जोखिम से बचने की भावना को मजबूत किया है। इस कारण निवेशकों की इक्विटी में निवेश की भूख सीमित हो गई है। सोमवार, 20 जुलाई 2026 को सेंसेक्स 442.93 अंक या 0.57 फीसदी गिरकर 77,708.52 पर बंद हुआ था। निफ्टी 95.80 अंक या 0.39 फीसदी गिरकर 24,238.50 पर समाप्त हुआ था। यह गिरावट बाहरी कारकों के प्रभाव को दशार्ती है।

चूंकि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (द1) के कॉरपोरेट नतीजों का सीजन धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, इसलिए बाजार में अब इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक-स्पेसिफिक एक्शन यानी चुनिंदा शेयरों में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। विश्लेषकों का मानना है कि जब तक ग्लोबल फ्रंट पर स्थितियां सामान्य नहीं होतीं और रुपये की कमजोरी दूर नहीं होती, तब तक व्यापक बाजार में एक सीमित रेंज के भीतर ही उतार-चढ़ाव होने की संभावना सबसे अधिक है।

ट्रंप के नए टैरिफ से बढ़ा अमेरिका-कनाडा तनाव, 30 दिन बाद लागू होंगे 50% आयात शुल्क

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के सामानों पर 50 फीसदी सीमा शुल्क लगा दिया है। ट्रंप ने कनाडा पर अमेरिकी कारों, शराब और डेयरी उत्पादों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। इस फैसले से दोनों देशों के बीच आर्थिक तनाव बढ़ने की आशंका है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कनाडा के ज्यादातर सामानों पर 50 फीसदी सीमा शुल्क (टैरिफ) लगा दिया है। ट्रंप का कहना है कि कनाडा अमेरिकी कारों, शराब और डेयरी उत्पादों के साथ गलत तरीके से भेदभाव करता है। इस फैसले से दोनों देशों के बीच आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। इससे महंगाई बढ़ सकती है और दोनों देशों के आपसी रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि चीन के अलावा कनाडा ही ऐसा देश था जिसने ट्रंप के पिछले शुल्कों का जवाब दिया था। इसलिए उसे जिम्मेदार ठहराना जरूरी है।

अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ट्रंप ने 1930 के व्यापार अधिनियम की धारा 338 के तहत तीन घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। पिछले साल कुछ डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस धारा को खत्म करने की मांग की थी क्योंकि उन्हें डर था कि ट्रंप इसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए कर सकते हैं। इस 50 फीसदी शुल्क से ऊर्जा उत्पाद, पोटाश, मछली और जरूरी खनिजों को बाहर रखा गया है। लेकिन इसमें वे सामान शामिल होंगे जिन्हें पहले कनाडा-अमेरिका-मैक्सिको समझौते (वरटउअ) के तहत सुरक्षा मिली हुई थी। अमेरिका ने इस समझौते को आगे नहीं बढ़ाया है, जिससे बातचीत का एक नया दौर शुरू हुआ जो 2036 तक चल सकता है।

व्हाइट हाउस के अनुसार, यह शुल्क 30 दिनों में लागू हो जाएगा। इसमें वाइन, हॉकी स्टिक से लेकर सीमेंट तक के उत्पाद शामिल होंगे। अधिकारी ने यह भी बताया कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कनाडा पर और शुल्क लगाने की संभावना तलाशने को कहा है, क्योंकि कनाडा के जंगलों की आग से अमेरिका की हवा खराब होती है।

रविवार को वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मैच देखा था। हालांकि, अधिकारियों ने साफ किया कि यह व्यापार पर चर्चा के लिए कोई आधिकारिक बैठक नहीं थी। कार्नी ने हमेशा ट्रंप को चुनौती दी है और वे दूसरे देशों के साथ कनाडा के व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। दोनों नेताओं के बीच रिश्ते काफी सामान्य रहे हैं। कार्नी ने पिछले साल कनाडा के हितों की रक्षा करने के वादे के साथ सत्ता संभाली थी। जनवरी में दावोस में कार्नी ने कहा था कि ताकतवर देश छोटे देशों को दबाने के लिए अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर ट्रंप ने कहा था कि कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा है।

ट्रंप का आरोप है कि कनाडा अमेरिकी कारों, शराब और पनीर के साथ भेदभाव करता है। दरअसल, कनाडा ने यह कदम तब उठाया था जब ट्रंप ने फेंटानिल तस्करी रोकने के बहाने कनाडा पर शुल्क लगाए थे। कनाडा ने अप्रैल 2025 से उन अमेरिकी वाहनों पर 25 फीसदी शुल्क लगाया जो समझौते के दायरे में नहीं आते। शराब के मामले में, पिछले साल कनाडा के दो प्रांतों को छोड़कर बाकी सभी ने अमेरिकी शराब की खरीद बंद कर दी थी। यह ट्रंप के शुल्कों और कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के उनके मजाक का जवाब था।

महत्वपूर्ण ख़बर

मुख्यमंत्री ने पूर्व राज्यपाल स्व. लालजी टंडन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की

- भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के पूर्व राज्यपाल तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन 'बाबूजी' की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि श्रद्धेय टंडन 'बाबूजी' की सादगी, सेवा और संगठन के मूल्यों से परिपूर्ण उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। राष्ट्र और समाज के प्रति लालजी टंडन का समर्पण सदैव जनसेवा के पथ पर हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा।

सीहोर के इछावर में पटवारी ऋषि यादव सस्पेंड

- सीहोर। सीहोर जिले की इछावर तहसील में पदस्थ पटवारी ऋषि यादव को जनप्रतिनिधि से अभद्र व्यवहार और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो रिकार्डिंग वायरल होने के बाद की गई।

प्रशासन के अनुसार, वायरल आडियो में पटवारी द्वारा जनप्रतिनिधि के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के साथ ही केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के राजस्व मंत्री के संबंध में भी टिप्पणी किए जाने की बात सामने आई है। मामला इछावर तहसील के हल्का नंबर-29, ग्राम रामदासी में पदस्थ पटवारी ऋषि यादव से जुड़ा है। ऑडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की थी। इछावर तहसीलदार ने 9 जुलाई को पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। पटवारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण करने के बाद प्रशासन ने उसे असंतोषजनक माना और इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की।

देश में सर्वश्रेष्ठ बने मध्यप्रदेश पुलिस: मुख्यमंत्री

अन्य प्रांतों की सीमाओं के निकट नशीले पदार्थों के अवैध परिवहन को रोकने के निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हाल ही में राज्य सरकार के पदोन्नति अभियान में पुलिस में सर्वाधिक पदोन्नतियां हुई हैं। इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाए रखने, अपराधों पर सख्त नियंत्रण और अधिक परिणाम लाने का कार्य किया जाए। मध्यप्रदेश पुलिस देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस मानी जाए, इसके लिए प्रयासों में कमी नहीं रखना है। नागरिकों में पुलिस के प्रति भरोसा है, इसे कायम रखें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस में विभिन्न स्तरों के लगभग 25 हजार पदों पर की गई पदोन्नति की कार्यवाही के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री संजय कुमार शुक्ल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री नीरज मंडलोई, पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्य हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि राजधानी से लेकर जिलों तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पुलिस बल आने वाले त्योहारों और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की आवश्यक तैयारी करें। नागरिकों को बेहतर कानून व्यवस्था का लाभ मिले। पुलिस अमला त्योहारों के अवसर पर मुस्तैद रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा नक्सलवाद के खात्मे के लिए जिस दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए उपलब्धि प्राप्त की गई, उसमें मध्यप्रदेश के नक्सल क्षेत्र को भी सामान्य बनाने में सफलता मिली है। नक्सलवाद के खत्म होने के पश्चात विकास कार्यों की गति बढ़ानी है और ऐसे इलाकों में पुलिस अमला भी सकारात्मक कार्यों से जुड़कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में नशामुक्ति अभियान का निरंतर क्रियान्वयन होता रहे। हाल ही में अभियान के अंतर्गत 'नशे से दूरी है जरूरी' स्लोगन को लोकप्रियता मिली है और नागरिकों ने नशामुक्ति की शपथ ली है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा निर्धारित नशामुक्ति अभियान के लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया जाए। नक्सलवाद से मुक्ति की तरह नशा मुक्ति के लिए तय समय-सीमा के पहले ही मध्यप्रदेश अच्छा कार्य करके दिखाए। इस क्रम में पुलिस विभाग, उच्च शिक्षा विभाग से समन्वय कर शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता बढ़ाने में सहयोगी बनें। श्रेष्ठ कार्य के लिए नशामुक्ति अभियान में योगदान देने वालों को पुरस्कृत भी करें। अन्य राज्यों से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों के अवैध परिवहन पर नियंत्रण किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों का विस्तार हो रहा है, इस नाते आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था भी जरूरी हो गई है। विभिन्न संस्थानों और उद्योग क्षेत्र के लिए एसआईएसएफ से लाइसेंसधारी सुरक्षा स्टाफ प्रदान करवाने का कार्य हो। भविष्य की दृष्टि से विकास के क्षेत्रों और सामाजिक स्तर पर उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की भी तैयारी रखें। वरिष्ठ अधिकारी हर समस्या के समाधान के प्रयास करें।

प्रमोशन और नियुक्ति का अभियान जारी रहे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस के लिए आवश्यक पदों की स्वीकृति दी गई है। राज्य शासन प्रदेश में नागरिकों के लिए शांति व्यवस्था और सदभाव के वातावरण को बनाए रखने के लिए पुलिस बल में पर्याप्त वृद्धि के निरंतर प्रयास कर रहा है। इस सिलसिले में लगभग 25 हजार पदोन्नतियां हाल ही में विशेष अभियान के अंतर्गत विभिन्न पदों पर की गई हैं। आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक और निरीक्षक के पदों पर बरसों से पदोन्नतियां नहीं हुई थीं। अन्य विभागों के साथ पुलिस विभाग में पदोन्नतियों का लाभ आमजन को बेहतर सेवाओं के रूप में मिलेगा। आगे भी पद रिक्त होने की स्थिति में डीपीसी कर प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इसके लिए कैलेंडर तैयार किया जाए। पद पूर्ति के लिए बैकलॉग समाप्त किया जाए। स्वीकृत पद भरने में विलंब नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इसी तरह पुलिस में प्रत्येक स्तर पर रिक्त पदों की पूर्ति का कार्य बिना विलंब किया जाए। प्रदेश की तीन विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया, भारिया की नियुक्तियों पर ध्यान दें। इन जनजातियों के रहवास के छह जिलों में योग्य युवाओं को पुलिस सहित विभिन्न सेवाओं में रुचि के अनुरूप भर्ती पर भी विचार किया जाए।

अब हर जिले में पुलिस बैंड में पर्याप्त पद

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक जिले का अपना बैंड ग्रुप तैयार हो जाए, यह सुनिश्चित करें। अधिकांश जिलों में पदों की पूर्ति की जा चुकी है। शेषजिलों में यह कार्य पूर्ण किया जाए। बैठक में पुलिस हाऊसिंग बोर्ड के कार्यों, वाहनों की आवश्यकता, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, सीन ऑफ क्राइम पर जाने के लिए एफएसएल की तरह व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।

मासूम बच्चों अव्यक्त और प्रेक्षा के परिजनों के साथ है सरकार : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर की डाक सहायक स्व. उर्मिला सैनी के मासूम बच्चों की स्कूली एवं उच्च शिक्षा की पढ़ाई-लिखाई के लिये 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मानवीय संवेदना जताते हुए इंदौर में घटित दुर्घटना में मासूम अव्यक्त (उम्र 7 वर्ष) और प्रेक्षा (उम्र 15 वर्ष) के सर से माँ श्रीमती उर्मिला सैनी का साया उठने के बाद मासूम बच्चों की शिक्षा और देखभाल के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मासूम प्रेक्षा ने नाना श्री सत्यनारायण मालाकार और अन्य परिजनों के साथ विधानसभा स्थित कक्ष में भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि वे स्वयं को बिल्कुल भी अकेला न समझें। सरकार मासूम बच्चों की शिक्षा के लिये हरसंभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बच्चों के नाम 5 लाख रुपए की एफडी होगी। एफडी की ब्याज की राशि बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में व्यय की जायेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को दिए दो ऑप्शन, 23 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

इंदौर। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को दो विकल्प दिए हैं। सोनम पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप है। यह निर्देश मेघालय सरकार की उस याचिका पर आया है, जिसमें सोनम को निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत और मेघालय हाईकोर्ट द्वारा उसे बरकरार रखने के फैसले को चुनौती दी गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने सोनम के वकील से कहा कि अदालत या तो मेघालय सरकार की अपील पर उनकी दलीलें सुनकर गुण-दोष के आधार पर फैसला करेगी, या फिर सोनम को फिलहाल आत्मसमर्पण करने का निर्देश देगी ताकि से पूछताछ हो सके और इस दौरान जमानत के मुद्दे पर विचार करेगी।

अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा, आपके पास दो विकल्प हैं। या तो हम गुण-दोष के आधार

पर आदेश पारित करेंगे, या हम आपसे आत्मसमर्पण करने को कहेंगे ताकि आपसे पूछताछ कर सकें - इस बीच हम जमानत के मामले पर विचार करेंगे। इस पर सोनम के वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा और अदालत को सूचित किया कि वह गुरुवार तक अपना जवाब दाखिल करेंगे। सुनवाई के दौरान अदालत ने घटना के बाद सोनम के आचरण पर भी सवाल उठाए और इस आरोप पर स्पष्टीकरण मांगा कि उसने पहले यह तर्क क्यों नहीं दिया था कि उसे गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए थे।

सोनम की जमानत का विरोध करते हुए मेघालय सरकार की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि सोनम ने पुलिस के सामने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया था, इसलिए वह बाद में इस आधार पर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दे सकती कि उसे गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए। उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारी मेमो में कोई भी चूक केवल एक लिपिकीय गलती थी। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने प्रस्तुत किया, यदि आरोपी रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तो गिरफ्तारी के कारण बताने की जरूरत नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है, तो वह इस आधार का उपयोग नहीं कर सकता कि उसे गिरफ्तारी के कारण नहीं दिए गए। अगर आरोपी खुद पुलिस के पास आता है, तो पुलिस के पास उसे अलग से गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं बनता।

मानसून में भी सूखने लगा भोपाल का बड़ा तालाब, 10 दिनों में 494 करोड़ लीटर पानी कम

भोपाल। मानसून के बीच भोपाल के बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ने के बजाय लगातार घट रहा है। पिछले 10 दिनों में तालाब का स्तर 0.45 फीट कम होकर 1659.90 फीट से 1659.45 फीट पर पहुंच गया है। अनुमान है कि इस दौरान तालाब से करीब 494 करोड़ लीटर पानी कम हो गया।

जुलाई में पिछले 10 वर्षों में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है, जब मानसून के दौरान जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा जल भंडारण शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए पर्याप्त है और फिलहाल किसी संकट की आशंका नहीं है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार तालाब के कैचमेंट क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं होने से प्राकृतिक जल प्रवाह नहीं मिल पाया। दूसरी ओर तेज धूप के कारण वाष्पीकरण बढ़ा और शहर की नियमित पेयजल आपूर्ति के लिए लगातार पानी निकाला जाता रहा। इन सभी कारणों का संयुक्त असर जलस्तर में गिरावट के रूप में सामने आया है। बड़े तालाब का फुल टैंक लेवल 1666.80 फीट है, जबकि वर्तमान स्तर इससे 7.35 फीट नीचे है। 2017 से 2025 तक के रिकॉर्ड बताते हैं कि जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में बड़े तालाब का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा।

बैतूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सहित समर्थकों पर मारपीट और एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज

बैतूल। शहर के जैन दादावाड़ी परिसर में 18 जुलाई को आयोजित कांग्रेस के संगठन सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद ने अब कानूनी रूप ले लिया है।

घटना के दो दिन बाद 20 जुलाई को देर शाम कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट, जातिसूचक गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और धक्का-मुक्की के आरोप लगाए हैं। दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।

पहले मामले में आमला निवासी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विजय पारधी की शिकायत पर पुलिस ने नवनीत मालवीय, पूर्व पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे, मनोज मालवे और सलमान खान के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 18 जुलाई की शाम करीब पांच बजे कार्यक्रम के दौरान आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज की, धक्का दिया, जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया तथा जान से मारने की धमकी दी गई।

वहीं दूसरे मामले में मनोज मालवे की शिकायत पर पुलिस ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा, विजय पारधी, हर्षवर्धन धोटे और मोनू बड़ोनिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कार्यक्रम के दौरान पूर्व पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे के अपमान की आशंका के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने उनका गला दबाया, लात-घूंसों से मारपीट की, जातिसूचक गालियां दीं तथा जान से मारने की धमकी दी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि घटना के बाद वरिष्ठ नेताओं ने मामले को शांत कराते हुए तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने की सलाह दी थी। कोतवाली पुलिस ने दोनों शिकायतों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(बी), 115(2), 351(2), 3(5) तथा एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

कोतवाली थाना प्रभारी देवकरण डहेरिया ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, उपलब्ध साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बायोमेट्रिक आधारित प्री-ऑथराइजेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

आयुष्मान भारत योजना में मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान

भोपाल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश को बेस्ट परफार्मिंग लार्ज स्टेट हाइयेस्ट प्री-ऑथोराइजेशंस विथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान योजना के अंतर्गत बायोमेट्रिक आधारित प्री-ऑथराइजेशन प्रक्रिया के प्रभावी, पारदर्शी एवं सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदान किया गया है। मध्यप्रदेश ने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि के लिये आयुष्मान भारत निरामयम् मध्यप्रदेश की टीम को बधाई दी है।

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, तकनीक आधारित सुशासन और जनहितकारी

कार्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए आयुष्मान भारत निरामयम् मध्यप्रदेश की टीम, जिला अधिकारियों, चिकित्सालयों और योजना से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में आयोजित राष्ट्रीय समीक्षा बैठक (चिंतन शिविर) में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव सुश्री पुण्य सलिला श्रीवास्तव द्वारा आयुष्मान भारत निरामयम्-मध्यप्रदेश के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अरविंद शाह को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सुनील कुमार बर्नवाल, संयुक्त सचिव श्री किरण गोपाल वास्का सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एवं यूआईडीएआई (आधार) के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

समान नागरिक संहिता से होगा सभी का भला : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर राम, रहीम, रविन्दर और रॉबिन सभी के लिए एक कानून की बात कही जा रही है।

इस संबंध में विधानसभा के पटल पर विधेयक प्रस्तुत हुआ है, जो वर्षाकालीन सत्र में कानून का रूप लेगा। मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने इसे 19 जुलाई को स्वीकृति दी थी। उम्मीद है, भविष्य में इसके लाभ से सभी को लाभान्वित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने टीवी चैनल प्रतिनिधियों से चर्चा में कहा कि समान नागरिक संहिता से सभी का भला सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता का लाभ सभी नागरिकों को प्राप्त होगा। सर्वाधिक लाभ मुस्लिम बहनों को होने वाला है। एक राष्ट्र, एक प्रधान, एक विधान और एक व्यवस्था के सिद्धांत पर कार्य हो रहा है। विवाह विच्छेद के बिना दूसरा विवाह नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रदेश में उच्च स्तरीय समिति के गठन और पूरे प्रदेश में विचार- विमर्श करने के साथ ही सभी समुदायों के नागरिकों से सुझाव प्राप्त किए गए। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं का समर्थन मिला था। प्रदेश की बेहतरी के लिए विपक्ष सहित सभी वर्गों और पक्षों से सहयोग और एकजुटता की आशा की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश एक नया रिकार्ड बनाने जा रहा है। अलग-अलग धर्मों के अनुयायियों के लिए एक विवाह का कानून लागू होगा। वैधानिक रूप से तलाक लिए बिना दूसरा विवाह गैर कानूनी रहेगा। इसके लिए दंड का कानून भी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वतंत्रता के पश्चात ही इसकी आवश्यकता थी। अब जब मध्यप्रदेश में यह कानून लागू होने वाला है तो निश्चित ही ऐसे अवसर पर समस्त प्रदेशवासी बधाई के पात्र हैं।

नशे के विरुद्ध इंदौर पुलिस ने रचा इतिहास

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व तथा पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा के मार्गदर्शन में प्रदेश में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे व्यापक जनजागरूकता अभियान ह्लनशे से दूरी है जरूरी 2.0ह्व को इंदौर में ऐतिहासिक जनसहभागिता मिली। पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में आयोजित विशाल जनजागरूकता कार्यक्रम में 8,534 विद्यार्थियों, सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों, खिलाड़ियों, नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों, पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों एवं नागरिकों ने एक साथ मानव श्रृंखला बनाकर नशे के विरुद्ध विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया।

भोपाल नगर निगम में 243 कर्मचारियों को मिला प्रमोशन

भोपाल। नगर निगम में कार्यरत 243 अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमोशन दिया गया है। निगम प्रशासन ने सोमवार देर शाम प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के विभिन्न पदों पर तीन दिन में पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों की सूची के आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश जारी होते हुए कर्मचारियों ने कमिश्नर सहित महापौर को धन्यवाद दिया। निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने पात्र कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की। इसके तहत प्रथम श्रेणी में एक अधिकारी को मुख्य अभियंता पद पर पदोन्नत किया गया है। द्वितीय श्रेणी में 13 सहायक यंत्री और दो स्वच्छता अधिकारियों को पदोन्नति मिली है। इसके अलावा तृतीय श्रेणी में एक उपयंत्री, तीन मुख्य स्वच्छता निरीक्षक, दो उद्यान निरीक्षक, तीन सहायक ग्रेड-एक, एक स्वच्छता निरीक्षक, 58 स्वच्छता पर्यवेक्षक, छह लेखापाल, 26 उप स्वास्थ्य

निरीक्षक, 14 सहायक ग्रेड-तीन, छह उद्यान पर्यवेक्षक, 42 उप स्वच्छता पर्यवेक्षक तथा 65 सहायक ग्रेड-2 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है।

निगम का मानना है कि पदोन्नति से कर्मचारियों को का उत्साह बढ़ेगा और निगम के कार्यों के संचालन में भी सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। राजकुमार, राजेश और जितेन्द्र बने मुख्य स्वच्छता निरीक्षण जारी आदेश के मुताबिक, रागिनी, विशाल, दीप, अनुज, संजय और प्रियंका को सहायक लेखापाल से लेखापाल, राजकुमार, राजेश, जितेन्द्र को स्वच्छता निरीक्षक से मुख्य स्वच्छता निरीक्षक, आशीष को स्वच्छता पर्यवेक्षक से स्वच्छता निरीक्षक बनाया गया है। शैलेष, रूखसाना, गगन, काशिफ, दीपक, अनीस, वर्षा, चेतन, अनस, मुताहिर, परवेज, सोहेल, वसीम, मोहन, कैलाश, सुभाष, शिशिर, अनिल, जैबा, सूफिया, युनूस, नीलेश, नरेश, रमन, कपिल और राजा को सहायक राजस्व निरीक्षक से राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।